- वर्ष-3
- अंक-104

रायपुर, शनिवार
09 दिसंबर 2023

- पृष्ठ-8
- मूल्य-3 रु.

samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› लहंगे के साथ बनवाएं यूनिक ....

प्रधानमंत्री बोले- जनता से लूटे गए पैसे की पाई-पाई लौटानी होगी

कांग्रेस सांसद का कुबेर खजाना मिला

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ओडिशा और झारखंड में कर छापे के दौरान पार्टी के एक सांसद धीरज प्रसाद साहू ठिकानों से करोड़ों रुपये नकद जब्त होने के बाद कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। एक्स को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के %भाषणों% को सुनें...। जनता से जो लूटा है, उसकी पाई-पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। राज्यसभा सांसद से जुड़े परिसरों पर छापेमारी के दौरान आयकर विभाग ने 200 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त की। ये बरामदगी ओडिशा के कई स्थानों से की गई थी।

छापेमारी बुधवार (6 दिसंबर) को शुरू हुई और यह रिपोर्ट लिखे जाने तक जारी थी। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक, ओडिशा में बौध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े परिसरों पर छापेमारी जारी रहेगी, जहां से नकदी बरामद की गई थी। शुक्रवार को, विभाग के अधिकारियों ने बोलांगीर जिले के सुदापाड़ा में छापेमारी के दौरान नकदी से भरे 150 से अधिक बैग बरामद किए। पूर्व आईटी कमिश्नर शरत चंद्र दाश ने कहा कि यह ओडिशा में आयकर विभाग द्वारा अब तक की सबसे बड़ी नकदी जब्ती हो सकती है। दाश ने कहा, मैंने राज्य में इतनी बड़ी मात्रा में नकदी की बरामदगी कभी नहीं देखी।

लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही प्रधानमंत्री ने 'एक्स' पर पोस्ट के जरिए विपक्षी दलों पर निशाना साधना तेज कर दिया है। मोदी ने पिछले दिनों आलोचकों पर निशाना साधते हुए कहा था कि वे अपने अहंकार, झूठ, निराशावाद और अज्ञानता की खुशफहमी में रह सकते हैं, लेकिन लोगों को उनके विभाजनकारी एजेंडे से सावधान रहना चाहिए क्योंकि 70 साल की पुरानी आदत इतनी आसानी से नहीं जा सकती। प्रधानमंत्री ने 'एक्स' पर एक पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया में यह बात कही थी।

कांग्रेस सांसद के ठिकानों से 200 करोड़ कैश बरामदै

नई दिल्ली। शुक्रवार को ओडिशा और झारखंड में कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े कई ठिकानों से 200 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी बरामद की गई। आयकर विभाग बुधवार (6 दिसंबर) से पड़ोसी राज्यों में साहू के परिसरों पर छापेमारी कर रहा था। खबर लिखे जाने तक छापेमारी जारी थी। सूत्रों के मुताबिक, ओडिशा में बौध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की गई, जहां से ज्यादातर नकदी बरामद की गई। अन्य स्थानों पर संबलपुर, बोलांगीर, टिटिलागढ़, बौध, सुंदरगढ़, राउरकेला और भुवनेश्वर में छापे मारे गए। वहीं, नोटों की गिनती अभी भी जारी है। इसी को लेकर भाजपा हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने आखिर कहां-कहां काली कमाई और नोट छिपा रखे की है? राहुल गांधी और सोनिया गांधी बार-बार नोटबंदी के खिलाफ क्यों बोलते हैं? झारखंड में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहां से 200 करोड़ रुपये से ज्यादा नकद मिली और गिनती जारी है... बैग और बोरियां कम पड़ गई. कांग्रेस, करप्शन(भ्रष्टाचार) और कैश, ये तीनों एक साथ चलते हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि मोहब्बत की दुकान पर भ्रष्टाचार का कारोबार चल रहा है.

महुआ माईत्रा के निष्कासन पर सियासी बवाल

विपक्ष ने बताया लोकतंत्र की हत्या, कानून से ऊपर कोई नहीं: भाजपा

नई दिल्ली। कैश फॉर क्वेरी मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को आज लोकसभा के सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। सदन में लोकसभा की आचार संहिता की रिपोर्ट को चर्चा के बाद मंजूरी दे दी गई जिसमें महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी। महुआ मोइत्रा के खिलाफ सदन में प्रश्न पूछने के बदले नगदी लेने के प्रत्यक्ष संलिप्तता के आरोप लगे थे। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा 15 अक्टूबर को शिकायत की गई थी। इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू हुई। हालांकि, इसको लेकर सियासी बवाल भी शुरू हो गया है। विपक्षी दलों के नेताओं ने इसे तानाशाही और लोकतंत्र के साथ विश्वासघात करार दिया। तो वहीं भाजपा ने कहा है कि महुआ मोइत्रा के प्रकरण से दुनिया में भारतीय सांसदों की छवि धूमिल हुई है।

मोइत्रा ने अपने इस निष्कासन की तुलना 'कंगारू अदालत' द्वारा सजा दिए जाने से करते हुए आरोप लगाया कि सरकार लोकसभा की आचार समिति को विपक्ष को झुकने के लिए मजबूर करने का हथियार बना रही है। उन्होंने कहा कि एथिक्स कमेटी के पास निष्कासित करने का कोई अधिकार

नहीं है...यह आपके (बीजेपी) अंत की शुरुआत है।

उन्होंने कहा कि अगर इस मोदी सरकार ने सोचा कि मुझे चुप कराकर वे अडानी मुद्दे को खत्म कर देंगे, मैं आपको यह बता दूं कि इस कंगारू कोर्ट ने पूरे भारत को केवल यह दिखाया है कि आपने जो जल्दबाजी और उचित प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है, वह दर्शाता है कि अडानी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, और आप एक महिला सांसद को समर्पण करने से रोकने के लिए उसे किस हद तक परेशान करेंगे।

तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इस कदम को देश के संसदीय लोकतंत्र के साथ ''विश्वासघात'' करार दिया। उन्होंने कहा कि आज मुझे बीजेपी पार्टी का रवैया देखकर दुख हो रहा है...

उन्होंने लोकतंत्र को कैसे धोखा दिया...उन्होंने महुआ को अपना रुख स्पष्ट करने की अनुमति नहीं दी। सरासर अन्याय हुआ है। ममता ने कहा कि मैं आपको बता रही हूं कि महुआ (मोइत्रा) परिस्थितियों की शिकार हुई हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं...हमारी पार्टी महुआ से साथ है हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी...यह लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ 'रिश्वत लेकर सवाल पूछने' के आरोप से जुड़े प्रकरण के चलते पूरी दुनिया में भारतीय सांसदों की छवि धूमिल हुई है। मोइत्रा के मामले से संबंधित आचार समिति की रिपोर्ट पर लोकसभा में चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद हिना गावित ने कहा कि मोइत्रा ने नियम तोड़ा है तथा कानून से ऊपर कोई नहीं है।

गावित ने कहा कि बहुत दुख हो रहा है कि ऐसे विषय पर चर्चा करनी पड़ रही है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2005 में इसी तरह के एक प्रकरण में कांग्रेस की सरकार के समय जिस दिन रिपोर्ट आई थी, उसी दिन 10 सांसदों को सदन से बाहर निकाला गया था और उन्हें भी अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया था।

भाजपा की दूरी, अजीत के लिए जरूरी

आखिर नवाब मलिक महाराष्ट्र में क्यों बने सियासी मजबूरी

मुंबई। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता नवाब मलिक को लेकर भाजपा और एनसीपी अजित गुट आमने-सामने है। यह पूरा मामला मीडिया के सामने तब आया जब महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने अपने समकक्ष अजित पवार को पत्र लिखकर साफ तौर पर कह दिया कि यह महायुती गठबंधन के लिए ठीक नहीं रहेगा। अजित को लिखे पत्र में फडणवीस ने कहा कि वह नवाब मलिक को अपने गुट में शामिल नहीं करें क्योंकि उनके खिलाफ कई बड़े गंभीर आरोप है। इसके बाद से अजित पवार गुट की ओर से भी पलटवार किया गया। फिलहाल भाजपा और अजित गुट के बीच तलवारें खींचती हुई दिखाई दे रही हैं।

कैसे शुरू हुआ मामला- दरअसल, महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र का 7 दिसंबर से आगाज हुआ। नवाब मलिक एनसीपी के विधायक हैं। वह शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए विधान भवन पहुंचे थे। शुरू में असमंजस की स्थिति रही कि वह किसी ओर बैठेंगे। लेकिन बाद में वह अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट के सदस्यों के बगल में पिछले पंक्ति के बेंच पर वह बैठे नजर आए। अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी नेताओं ने नवाब मलिक का जोरदार स्वागत भी किया। यहीं से नवाब मलिक को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। विपक्षी दलों के नेताओं में कानाफूसी भी देखने को मिली। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता अंबादास दानवे और सुषमा अंधारे ने मलिक के सत्ता पक्ष में शामिल होने को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। सत्ता पक्ष में बैठे नवाब मलिक की फोटो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। फडणवीस ने अजित पवार को लिखे अपने पत्र में कहा कि मलिक को एक विधायक के रूप में विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। उन्होंने कहा ,'' हमारी (भाजपा) उनके खिलाफ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या द्वेष नहीं है।

हार की समीक्षा के बाद बोली कुमारी सैलजा हम निराश है लेकिन हताश नहीं

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिली कारारी हार के बाद आज प्रभारी सैलजा ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 'इस चुनाव के बारे में समीक्षा की अपने विचार रखें, बहुत ही स्पष्ट रूप से सब ने अपने अपने व्यूज यहां पर दिए। उन्होंने कहा कि ये बात जरूर है कि हम चुनाव हारे लेकिन साथ में ये बात मैं कहूंगी कि चाहे वो नेशनल मीडिया हो या चाहे रिजनल मीडिया हो, कोई भी ऐजेंसी हो हर एक ने कहा था कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं और कही किसी हद तक आप सही साबित भी हुए, क्योंकि हमारा वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ।

प्रमुख समाचार

मैं विद्यार्थी परिषद का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हूं: एबीवीपी के अधिवेशन में बोले शाह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को खुद को विद्यार्थी परिषद का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बताते हुए कहा कि युवाशक्ति किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है। वह दिल्ली के बुराड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत को अपनाया है और दुनिया भर में इसका उचित श्रेय दिया है! मोदी जी ने संकल्प लिया है कि आने वाले 25 वर्षों में भारत विश्व गुरु बनेगा। शाह ने कहा कि विद्यार्थी परिषद ने अनेक मौकों पर संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि ज्ञान, शील, एकता के अपने मूलमंत्र को आत्मसात करते हुए, धैर्यपूर्वक एक पथ का निर्माण किया और देश के सामने, शिक्षा जगत के सामने एवं देश की सीमाओं के सामने जो भी चुनौतियां आईं, उस हर चुनौती के साथ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है। ये देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 1949 से 2023 तक की यात्रा देश के विकास के साथ-साथ जुड़ी है।

विदेशों से आ रहे चंदे के कारण राम मंदिर का खजाना लगातार बढ़ रहा

अयोध्या। अयोध्या में बन रहे भव्य श्रीराम मंदिर का पहला चरण पूरा होने वाला है। पहले चरण का निर्माण कार्य अपने अंतिम स्तर पर पहुंच चुका है। राम मंदिर के भव्य निर्माण को पूरा होता देखने के लिए श्रद्धालु बेहद उत्सुक है। अयोध्या में बना रहे श्री राम मंदिर के पहले चरण का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है इसके बाद भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में चंदा दे कर रहे हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए दान अब भी लगातार आ रहा है। इसकी जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से दी गई है। ट्रस्ट का कहना है कि राम मंदिर केक खजाने में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। मंदिर की खजाने के संबंध में ट्रस्ट की कोषाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि हमें एफसीआई से भी प्रमाण पत्र मिल चुका है। प्रमाण पत्र मिलने के बाद राम मंदिर निर्माण के लिए विदेश से भी चंदा भरपूर मात्रा में आ रहा है। इस संबंध में कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी ने कहा कि रामलाल के लिए आ रहे कोष के बारे में लोगों को जानने की काफी जिज्ञासा है। भगवान राम लाल का कोष लगातार बढ़ता जा रहा है। मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने को है और कोष भी लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वामी गोविंद देवगिरी ने बताया कि मंदिर निर्माण के लिए विदेश से भी चंदा आने लगा है।

हद खतरनाक है 'मेफ्टाल' पेनकिलर का सेवन, सरकार ने अलर्ट किया जारी

नई दिल्ली। आमतौर पर भारतीय घरों में हल्की तबियत के बिगड़ने पर लोग घर में ही पेनकिलर या अन्य दवाइयां ले लेते है। सिर दर्द, बदन दर्द या शरीर के किसी अन्य हिस्से में होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति डॉक्टर की सलाह लिए बिना ही पेनकिलर का सेवन कर लेते है। मगर ऐसा करना लोगों की सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। इसकी घोषणा भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने भी कर दी है।

आयोग ने जानकारी दी है कि कई तरह के दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग मेफ्टाल दवाई का उपयोग करते है। इस दवाई का उपयोग करने के संबंध में आयोग ने अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट में कहा गया है कि मेफ्टाल दवाई का अधिक सेवन करने से एलर्जी अधिक होने का खतरा रहता है। ये दवाई ड्रेस सिंड्रोम जैसी एलर्डी को बढ़ा सकती है। ये एलर्जी शरीर में हो सकती है, जो काफी परेशान कर सकती है।

अकबरुद्दीन ओवैसी बने प्रोटेम स्पीकर, भाजपा विधायक टी राजा सिंह बोले- जब तक जिंदा हूं...

हैदराबाद। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को शुक्रवार को तीसरे तेलंगाना राज्य विधानसभा के पहले सत्र के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया, जो शनिवार से शुरू होने वाला है। राज्य विधानमंडल द्वारा जारी एक नोटिस में बताया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेलंगाना के राज्यपाल श्री अकबर उद्दीन ओवेसी को तेलंगाना विधान सभा के सदस्य के रूप में तेलंगाना विधान सभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करते हैं। जब तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 178 के तहत एक अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है और वह वह व्यक्ति भी होता है जिसके समक्ष विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 के तहत अपेक्षित शपथ या प्रतिज्ञान करेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे। प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी भूमिका निभाता है, नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ लेने और स्पीकर चुने जाने तक विधानसभा सत्र का संचालन करता है।

लालदुहोमा ने संभाली मिजोरम की कमान

त्रिपुरा। जोराम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) के नेता लालदुहोमा ने शुक्रवार को मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति ने लालदुहोमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जेडपीएम के 11 अन्य नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में आयोजित किया गया जहां मिजो नेशनल फ्रंट के नेता और निवर्तमान मुख्यमंत्री जोरमथांगा भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में एमएनएफ के विधायक दल के नेता लालचंदमा राल्ते समेत सभी विधायक शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री ललथनहवला भी इस अवसर पर मौजूद रहे। मंगलवार को जेडपीएम विधायक दल ने लालदुहोमा को अपना नेता और के. सपडांगा को उपनेता चुना था। हम आपको बता दें कि मिजोरम में 40 सदस्यीय विधानसभा है और राज्य में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री हो सकते हैं। जेडपीएम ने सात नवंबर को हुए राज्य विधानसभा चुनाव में 40 में से 27 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके अलावा, मिजोरम विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाली एमएनएफ ने बुधवार को अपने अध्यक्ष जोरमथांगा का इस्तीफा अस्वीकार कर दिया>

बेमतलब है हिन्दू वोटबैंक की मुस्लिम वोटबैंक से तुलना

संजय तिवारी

भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी पढ़े लिखे सेकुलर लोग अक्सर यह सवाल उठाते हैं कि हिन्दू जिस तरह से भाजपा और मोदी के पीछे धर्म के नाम पर वोटबैंक बन रहे हैं, वह उन्हें एक दिन बर्बाद कर देगा। इसके पीछे उनका तर्क होता है कि पाकिस्तान में यह प्रयोग हुआ और रिलीजन को गवर्नेन्स से मिक्स कर दिया गया जिसका नतीजा पाकिस्तानी अवाम की बदहाली के रूप में सामने आया है। आज नहीं तो कल भारत के लोगों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या ये तुलना सही है? क्या सचमुच भारत को भी एक दिन वैसी ही कीमत चुकानी पड़ेगी जैसी पाकिस्तान को चुकानी पड़ रही है?

हर व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा करना लोकतंत्र का बुनियादी स्वभाव होता है। इसमें कई तरह के मतभेद हो सकते हैं कि किसी लोकतांत्रिक प्रणाली में किस तरह के नियम कानून बनाये जाते हैं जिससे व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। या फिर वो मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों के कितना अनुकूल हैं। लेकिन लोकतंत्र के मूल में नागरिक होते हैं। लोकतंत्र उन्हीं के अधिकारों और कर्तव्यों में समता स्थापित करनेवाली व्यवस्था है ताकि एक नागरिक दूसरे नागरिक का शोषण न कर सके।

बहुदलीय लोकतंत्र में हालांकि इसका विकृत रुप भारत पाकिस्तान में प्रचलित हुआ और सिद्धांत रूप में हम जिन बातों का विरोध करते हैं व्यवहारगत रूप से उसी का प्रचार कर रहे होते हैं। जैसे लोकतंत्र में जाति धर्म के नाम पर नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए लेकिन एक तरह के भेदभाव को खत्म करने के लिए हमारे नेताओं ने दूसरे तरह के भेदभाव को जन्म दे दिया। भारत और पाकिस्तान दोनों ही जगहों पर ये काम खूब जमकर किया गया है। भारत में अगर मॉइनारिटी और दलित अधिकारों के नाम पर वर्ग विभाजन को मजबूत किया गया तो पाकिस्तान में सुन्नी बहुसंख्यकवाद हावी हुआ और उसने दबाव डालकर अहमदिया, हिन्दू और क्रिश्चियन मॉइनारिटी को कोने में धकेलने का काम किया।

1947 के बाद से ही भारत में जहां नागरिकों के बीच भेदभाव को खत्म करने के प्रयास शुरु हुए वहीं पाकिस्तान में नागरिकों के बीच भेदभाव बढाने के प्रयास रंग लाये। शुरुआत सेकुलर और सोशलिस्ट तरीके से हुई जो वर्गीय और जातीय विभाजन पर जोर दे रही थी लेकिन इसकी प्रतिक्रिया में जिस हिन्दू बहुसंख्यकवाद का उदय हुआ वह सबको हिन्दू बताकर उन्हें एकता के सूत्र में बांध रहा था। इसके उलट पाकिस्तान में अहमदिया, शिया को गैर मुस्लिम बताकर मुसलमानों से ही अलग थलग किया गया तो हिन्दू, क्रिश्चियन, सिख और अहमदिया को गैर मुस्लिम कहकर पाकिस्तान के शीर्ष पदों पर पहुंचने से ही कानूनन रोक दिया गया।

इसलिए भारत का हिन्दू बहुसंख्यकवाद जहां नागरिक एकता को मजबूत करता है वहीं पाकिस्तान का सुन्नी बहुसंख्यकवाद मुसलमानों में ही भेद पैदा करता है। इसलिए भारत के बहुसंख्यकवाद को पाकिस्तान के बहुसंख्यकवाद से तुलना करना ही बेमतलब और गैर जरूरी है। अब तो आरएसएस भी यह कहने लगा है कि हिन्दू की वृहद पहचान में ईसाई और मुस्लिम भी शामिल हैं क्योंकि यह इस धरती से जुड़ी पहचान है। जबकि पाकिस्तान में सुन्नी बहुसंख्यकवाद अहमदिया को मुसलमान मानने तक तो तैयार नहीं है।

लोकतंत्र एक ऐसी विकेन्द्रित व्यवस्था है जो संगठित रूप से काम करती है। यह एक विरोधाभास है लेकिन सच है। लोकतंत्र दलों के जरिए संचालित होते हैं और दल एक प्रकार के संगठित गिरोह में परिवर्तित हो जाते हैं। जहां कहीं भी संगठनवाद प्रभावी होगा वहां सबसे पहला खतरा लोकतंत्र के सामने ही आता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भाजपा एक संगठन से निकली पार्टी है जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। इसलिए अगर भाजपा धार्मिक गोलबंदी करती है जहां मतदाता विवेक की बजाय भीड़ की मानसिकता से वोट करता है तो लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा होता है।

लेकिन ऐसा है नहीं। आरएसएस हिन्दुओं के बीच संगठन का काम करता है लेकिन वह समूचे हिन्दू समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता। ऐसे लाखों करोड़ों हिन्दूवादी हैं जो आरएसएस से नहीं जुड़े हैं लेकिन राजनीति में धर्म के अपमान को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। क्या उनको भी आरएसएस का वर्कर कहा जा सकता है? नहीं। वो हिन्दुत्व की राजनीति को पसंद तो करते हैं, राजनीतिक रूप से भाजपा के समर्थक भी हैं लेकिन आरएसएस से उनका कोई जुड़ाव नहीं है। इसलिए इस बात की पूरी संभावना हमेशा है कि वो मुस्लिमों की तरह किसी फतवे से प्रभावित होकर वोट नहीं करेंगे।

धर्म के नाम हिन्दुओं को उस तरह कट्टर बनाया ही नहीं जा सकता जैसा कि मुस्लिमों को बनाया जाता है। मुस्लिमों में मुल्ला मौलवी उन्हें जो समझाते हैं वो मान जाते हैं और उसी हिसाब से व्यवहार करते हैं। जबकि हिन्दुओं को राजनीतिक और सामाजिक रूप से कोई गवर्न करने की गारंटी नहीं ले सकता। असंगठित जीवन जीने वाले स्वभाव के बाद भी हिन्दू में साथ आने की सामूहिक चेतना तो जाग रही है लेकिन वह मुसलमानों की तरह किसी भीड़तंत्र में परिवर्तित नहीं हो रही है। यही मुस्लिम वोटबैंक और हिन्दू वोटबैंक का बुनियादी अंतर है।

भाजपा हो या अब दस साल से नरेन्द्र मोदी का शासन। उन पर हिन्दू कट्टरता का आरोप तो विपक्ष बहुत लगाता है लेकिन एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है जब प्रशासनिक निर्णय में उन्होंने धार्मिक भेदभाव किया हो। इसके उलट जो मॉइनॉरिटी स्कीम हैं वो पहले की भांति जस की तस जारी हैं। उनका बजट भी घटाने की बजाय बढाया ही गया है। हां, सामान्य प्रशासन में जो अल्पसंख्यक तुष्टिकरण होता था, उसे जरूर खत्म करने का प्रयास किया गया है।

असल में धर्म की दीन से तुलना ही एक गंभीर वैचारिक समस्या है। इस्लाम एक दीन या सिस्टम है जो इस्लामिक कायदे वाले शासन की वकालत करता है। इस शासन में मुस्लिम और गैर मुस्लिम का भेद किया जाता है। मुस्लिमों के लिए एक इस्लामिक शासन में जो लाभ रहते हैं उससे गैर मुस्लिमों को अलग रखा जाता है। इसलिए इस्लामिक स्टेट में नागरिकों के बीच भेदभाव उसका बुनियादी चरित्र है।

अवैध रूप से चल रही सिलेंडर की बिक्री और रिफलिंग पर खाद्य विभाग ने मारा छापा

■ घरों और दुकानों से बड़ी संख्या में सिलेंडर जब्त

बलौदाबाजार। जिला मुख्यालय में खाद्य विभाग ने कलेक्टर चंदन कुमार के निर्देश पर अवैध रूप से गैस सिलेंडर की बिक्री और रिफिलिंग पर छापेमारी की कार्रवाई की है। इस दौरान शहर और बलौदाबाजार के ग्राम छुईहा में सड़क किनारे मकान से लगभग 100 घरेलू, व्यवसायिक उपयोग सिलेंडर और गैस रिफलिंग करने का सामान जब्त किया गया।

सारे नियम कानून कायदों को ताक में रखकर सड़क किनारे जनरल स्टोर और जूते चप्पल बिक्री करने वाले दुकान की आड़ में खुलेआम सड़क पर रखकर गैस सिलेंडर की अवैध बिक्री की जा रही थी। खाद्य विभाग को सूचना मिलने पर आज कार्रवाई करते हुए दोनों दुकानों से लगभग 21 सिलेंडर भरे और खाली जब्त की गई। वहीं बलौदाबाजार भाटापारा रोड में स्थित एक मकान में अवैध सिलेंडर रखे होने की सूचना पर कार्रवाई की गई। जहां 76 सिलेंडर एचपी और इण्डेन कंपनी के भरे व खाली मिले हैं। साथ ही नये छोटे गैस सिलेंडर और गैस रिफलिंग करने की मशीन भी मिली है। यहां स्थिति देखकर लग रहा था कि काफी वर्षों से रिफलिंग का कार्य किया जा रहा था और रिफलिंग कर सिलेंडर बेचा जा रहा था।

बलौदाबाजार भाटापारा रोड के ग्राम छुईहा मे स्थित मकान में दबिश पर खाद्य विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं जब शटर खोला गया तो अधिकारियों की आंखे फटी रह गई। यहां बड़े पैमाने पर नियम कानूनों को ताक में रखकर बड़े गैस सिलेंडर से छोटे गैस सिलेंडर में गैस भरने की सामग्री, मशीन और खाली गैस सिलेंडर मिले हैं। जिसके बाद जिला खाली अधिकारी सहित खाली विभाग अमला कार्रवाई में जुट गया है।

जिला खाद्य अधिकारी विमल दुबे ने बताया कि अवैध रूप से गैस सिलेंडर मिलने की सूचना मिलने पर कलेक्टर के निर्देश पर आज खाली विभाग की टीम द्वारा बलौदाबाजार नगर के दो दुकानों में 21 खाली और भरे सिलेंडर मिले हैं। साथ ही बलौदाबाजार भाटापारा रोड में ग्राम छुईहा के पास गोदाम नुमा मकान में 76 खाली और भरे सिलेंडर प्राप्त हुए तथा रिफलिंग करने की मशीन भी मिली है। जिसपर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल खाद्य विभाग के अधिकारी यह नहीं बता पा रहे हैं कि उक्त मकान किसका है और गैस सिलेंडर रिफलिंग करने का काम कबसे किया जा रहा है। इसकी जांच की जा रही है और दोषी के विरुद्ध खाद्य विभाग के नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

गौरतलब यह है कि एक तरफ एजेंसियों में सिलेंडर की कमी बताई जाती है। वहीं दूसरी तरफ दुकानों के माध्यम से खुले आम गैस सिलेंडर की बिक्री और अवैध रूप से सिलेंडर रिफलिंग कर बेचे जा रहे हैं। इस तरह की अवैध रिफलिंग करना एक बड़ी घटना को भी जन्म दे सकता है। सवाल यह उठता है कि इन अवैध सिलेंडर बिक्री करने वालों को यह सिलेंडर कहा से मिलता है। अब देखने वाली बात होगी कि खाद्य विभाग कितनी पारदर्शिता और सच्चाई से कार्रवाई करती है। फिलहाल खाद्य विभाग ने जिला मुख्यालय में होने वाली घटना को टालने में कामयाबी पाई है।

ओडिशा से परिवहन किये जा रहे 340 बोरी अवैध धान जब्त

■ मंडी अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई

जगदलपुर। राज्य शासन के निर्देशानुसार खरीफ विपणन सीजन 2023-24 के तहत जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। कलेक्टर विजय दयाराम के. के निर्देश पर जिले में धान खरीदी के लिए सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने सहित धान खरीदी की निरंतर जांच की जा रही है।

जिले के सीमावर्ती इलाकों में अवैध धान परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, जिसके फलस्वरूप जांच दलों द्वारा विगत रात्रि उड़ीसा राज्य की सीमा में तीन मालवाहक वाहनों से करीब 340 बोरी अवैध धान जब्त किया गया है। उक्त जब्त धान सहित वाहनों को नगरनार पुलिस थाने में सुपुर्द कर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।

जांच दल के प्रभारी अधिकारी नायब तहसीलदार लखीराम पांडेय ने बताया कि कलेक्टर विजय दयाराम के. निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जगदलपुर नंद चैबे के मार्गदर्शन में गठित जांच दल द्वारा सात दिसंबर की रात में ओडिशा राज्य के सीमा पर निगरानी रखकर सघन जांच करने के दौरान चोकावाड़ा माचकोट रोड रेलवे क्रॉसिंग में अशोक लिलेंड मालवाहक वाहन क्रमांक सीजी-केआर 1751 से 40 बोरी अवैध धान बस्तर जिले में परिवहन करते हुए पकड़ा गया।

इसी तरह धनपूंजी जांच नाके में दो टाटा 709 मालवाहक वाहन क्रमांक ओडी 10-0158 तथा ओडी 10 पी-6937 से डेढ़-डेढ़ सौ बोरी कुल 300 बोरी अवैध धान का बस्तर जिले में परिवहन करते हुए पकड़ा गया। उक्त जब्त सभी धान और वाहनों को नगरनार पुलिस थाने के सुपुर्द कर एफआईआर दर्ज कराया गया है। मंडी सचिव द्वारा मंडी अधिनियम के तहत संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

इस कार्रवाई के लिए कलेक्टर विजय ने जांच दल में शामिल अधिकारी-कर्मचारियों की सराहना करते हुए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा सघन जांच किये जाने की दिशा में उत्साहवर्धन किए हैं।

सीतापुर के धान खरीदी केंद्र में भीग रहे धान, समिति प्रबंधक की लापरवाही

एक्शन मोड में नए विधायक रामकुमार टोप्पो

अंबिकापुर। सरगुजा संभाग में बीते दो दिनों से लगातार रुक-रुक कर बारिश हो रही है। जिसकी वजह है चक्रवाती तूफान मिचोंग। इस तूफान की वजह से लागातार तीन दिनों से अंबिकापुर में रुक रूक कर बारिश हो रही है। इस बीच यहां धान खरीदी केंद्रों में समिति प्रबंधक की गंभीर लापरवाही सामने आ रही है। बारिश से धान भीग रहें हैं, बावजूद इसके यहां धान को बचाने के लिए समिति प्रबंधक गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं।

धान खरीदी केंद्रों में भीग रहे धान

पूरा मामला अंबिकापुर जिले के सीतापुर धान खरीदी केंद्र का है। जहां लगातार हो रही बेमौसम बारिश से समिति में धान भीग रहा है। समिति प्रबंधक के द्वारा धान की खेप को बारिश से बचाने के लिए आधा-अधूरा तिरपाल लगाकर धान को ढंकने की कोशिश की गई है, जो नाकाफी है। बारिश से धान भीग रहें है। इस संबंध में जब समिति के कंप्यूटर ऑपरेटर से बातचीत की गई तो उसने बताया कि बारिश से धान को बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तिरपाल की कमी होने से धान भीग रहा है।

विधायक रामकुमार ने लिया संज्ञान

इस संबंध में सीतापुर विधानसभा सीट के नवनिर्वाचित विधायक रामकुमार टोप्पो से बात की गई। उन्होंने कहा, मैं आज ही क्षेत्र में आया हूं और धान न भीगे इसके लिए अधिकारियों से मीटिंग करता हूं। इस ओर ध्यान देंगे, ताकि धान न भीगे। सीतापुर एसडीएम रवि राही ने सीतापुर धान खरीदी केंद्र में तत्काल टीम भेजकर इसकी जांच कराने का निर्देश देने की बात कही है। ताकि धान न भीगे। इस मामले में आगे लापरवाही होने पर एसडीएम ने समिति प्रबंधक पर कारवाई करने की बात कही है।

सहायक शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

10 दिन के भीतर ज्वाइनिंग देने सरकार को निर्देश

बिलासपुर। सहायक शिक्षकों की पोस्टिंग के मामले में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने सरकार को 10 दिनों के भीतर शिक्षकों को संशोधित शालाओं में ज्वाइनिंग देने के निर्देश दिया है। इससे पहले संशोधन पर राज्य सरकार ने निरस्तीकरण की कार्रवाई की थी, जिसके खिलाफ कई शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।

दरअसल, प्रदेश के सहायक शिक्षकों को शिक्षकों के पदों में प्रमोशन दिया गया था। प्रमोशन के बाद उनका पदांकन कर विभिन्न स्कूलों में करते हुए पोस्टिंग दी गई थी। सैकड़ों शिक्षकों को दूरस्थ स्कूलों में पदस्थ किया गया था, जिसके खिलाफ शिक्षा विभाग में आवेदन देकर अपनी पोस्टिंग संशोधित करवाते हुए पास के स्कूलों में करवा ली थी। संशोधन आदेश के एवज में लाखों रुपए के लेन-देन के आरोपों के बाद सरकार ने संशोधन आदेश को 4 सितंबर को निरस्त कर शिक्षकों को एकतरफा कार्यमुक्त कर दिया था।

संशोधन आदेश निरस्तीकरण को लेकर सैकड़ों शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अरविंद चंदेल ने ट्रांसफर पर 11 सितंबर को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे। कोर्ट के निर्देश के बाद शिक्षक ना तो पदांकन वाली शालाओं में ज्वाइन कर पा रहे थे, और न ही संशोधित स्कूलों में। इससे शिक्षकों को वेतन भी जारी नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए एक बार फिर शिक्षक कोर्ट पहुंचे थे।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्षदों की कुर्सी खतरे में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में भाजपा

दुर्ग भिलाई। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद अब कांग्रेस पार्षदों की कुर्सी खतरे में दिख रही है। भाजपा की जीत के साथ नगरीय निकायों में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। फिलहाल दुर्ग और भिलाई नगर निगम में कांग्रेस की सत्ता है। लेकिन प्रदेश में भाजपा की सत्ता होने के कारण बीजेपी पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में हैं। उनको उम्मीद है निर्दलीय सत्ता के साथ ही रहना चाहेंगे। इसलिए उनको साधना कठिन नहीं है। इसके साथ ही असंतुष्ट कांग्रेस पार्षदों को भी पाले में लाया जा सकता है।

दरअसल, भिलाई नगर निगम में सत्ताधारी कांग्रेस सतर्क है। भाजपा यहां अविश्वास प्रस्ताव लाए, इसके पहले ही कांग्रेस अपने पार्षदों को जोड़कर रखने में जुट गई है। दूसरी ओर भाजपा के पार्षद सरकार गठन होने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद वे शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कह रहे हैं। वहीं, भिलाई नगर निगम के निर्दलीय पार्षदों की अहमियत बढ़ गई है।

नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने कहा भिलाई नगर निगम में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के निर्देश के बाद चर्चा की जाएगी। दो सालों में बहुत सारे पार्षद अपमानित महसूस किए हैं। वह सभी पार्षद हमारे संपर्क में हैं। साथ ही निर्दलीय पार्षद भी संपर्क में हैं। निगम में 9 निर्दलीय पार्षद हैं। इसमें योगेश साहू, हरिओम तिवारी, राजेंद्र कुमार, रानू साहू, रामानंद मौर्य, अनिता अजय साहू, संतोष नाथ सिंह, इंजीनियर सलमान, वशिष्ठ नारायण मिश्रा शामिल हैं। इन पार्षदों में कुछ को कांग्रेस ने जोन अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। वहीं, कुछ भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़े और निर्दलीय चुनाव जीते। उनकी भाजपा में वापसी की संभावना जताई जा रही है। भिलाई नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के 24 और कांग्रेस के पास 37 पार्षद हैं। भाजपा को अगर बहुमत चाहिए तो कम से कम और 12 पार्षदों की जरूरत है। ऐसे में वे पहले निर्दलीय, इसके बाद कांग्रेसियों पर डोरे डालेंगे। सत्ता परिवर्तन होने के बाद निर्दलीयों के इधर-उधर होने की आशंका है। कांग्रेस के महापौर नीरज पाल ने कहा हमारे साथ बहुमत है। हमारे साथ जो भी जुड़े हैं। सब एक साथ हैं। कोई भी अविश्वास प्रस्ताव काम नहीं आएगा। सरकार हमारी ही रहेगी।

वार्ड में अधिक काम करवाने और लाभ के लिए वे सरकार के साथ जा सकते हैं। निर्दलीय पार्षदों को भाजपा के खेमें में जाने से एमआईसी और जोन अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी मिल सकती है। इस लालच में वे भाजपा के साथ जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास महापौर के तौर पर बड़े चेहरों की कमी नहीं है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

सुंदर नगर (घोट) के सरपंच ने मूड़वाया मूंछ

नवापारा-राजिम। एक दांव अभनपुर ब्लॉक के ग्राम सुंदर नगर (घोट) के सरपंच सेवाराम यादव ने खेला था कि भाजपा प्रत्याशी इंद्र कुमार साहू 26000 वोट से जीतेंगे अगर वे एक वोट से भी कम से जीतेंगे तो मैं अपने मूंछ मुड़वाऊंगा। चुनाव परिणाम आने के बाद इंद्र कुमार साहू 15553 मतों से विजयी हुए। अपने दावे पर फेल हो गए, जिसके बाद सरपंच ने मूंछ मुड़वा ली। सरपंच सेवाराम भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता है। उनका गांव में जोरदार जनाधार है। लेकिन अपने दावे पर फेल होने पर खुशी-खुशी मुंछ मुड़वा ली है, जिसकी क्षेत्र में काफी चर्चा हो रही है।

नपा अध्यक्ष के खिलाफ भाजपा लाएगी अविश्वास प्रस्ताव

महासमुंद। सरायपाली नगर पालिका अध्यक्ष अमृत पटेल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पार्षदों ने ज्ञापन सौंपा है। पार्षदों ने अध्यक्ष पर पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, परिवार सहायता और श्रद्धांजलि योजना के साथ पार्षदों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। बता दें कि, सरायपाली नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए भाजपा के 4 पार्षदों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पार्षदों ने अध्यक्ष पर पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, परिवार सहायता और श्रद्धांजलि योजना के हितग्राहियों को समय पर लाभ नहीं देने और पार्षदों के साथ दुर्व्यवहार करने भी आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार, नगर पालिका सरायपाली के 15 वार्डों में 9 भाजपा के, 4 कांग्रेस के और 2 निर्दलीय पार्षद हैं, जिसमें भाजपा के पास 11 पार्षदों का समर्थन है।

डीईओ ने किया स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण

बेमेतरा। जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा अरविन्द कुमार मिश्रा द्वारा विकासखण्ड बेरला के शाउमा विद्यालय आनंदगांव, खुड़मुड़ी, शापूमा शाला खर्रा, शासकीय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय कठिया रांका तथा विकासखण्ड नवागढ़ के शासकीय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय नांदघाट का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आनंदगांव के निरीक्षण के दौरान सभी शिक्षक कक्षा अध्यापन के बजाय बोर्ड का काम करते पाए गए। विद्यालय के पाठकान के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि पाठकान में अर्ध दिवसीय आकस्मिक अवकाश की प्रविष्टि नहीं की जाती। पूर्व के तिथियों के अनेक अर्ध दिवसीय आकस्मिक अवकाश के आवेदन पाठकान में दबे पाए गए जिनकी प्रविष्टि पाठकान में नहीं की गई थी। विद्यालय के प्राचार्य के द्वारा जानकारी दी गई कि 02 बार नोटिस जारी किए जाने के बाद भी विरेन्द्र कुमार टण्डन द्वारा अध्यापन कार्य नहीं कराया जाता इस पर डी.ई.ओ. द्वारा टण्डन के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित किए जाने के निर्देश दिए गए।

आरंग में प्रशासन ने हटाए अवैध ठेले-गुमटियां

आरंग। इन दिनों आरंग में प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई चर्चा का विषय बना हुआ है। शराब दुकान के आसपास अवैध चखना दुकानों और कॉलेज चौक पर अवैध ठेले-गुमटियों को हटाने के बाद एक तरफ प्रशासन के इस कार्य की तारीफ हो रही है। वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि जिस प्रकार प्रशासन ने अवैध दुकानों और ठेले-गुमटियों पर बुलडोजर चलाया उसी प्रकार आरंग नगर पालिका के विभिन्न वार्डों में शासकीय जमीनों पर हुए, कब्जे और अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि आरंग नगर पालिका अंतर्गत विभिन्न जगहों पर शासकीय जमीनों पर कब्जा करके उसमें अवैध निर्माण किया गया है। इसमें कई रसूखदार भी हैं, जिन्होंने धन और बल का प्रयोग कर शासकीय जमीनों पर अतिक्रमण कर दुकान और काम्पलेक्स तक बना डाले हैं। इस मामले में आरंग नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी होरीसिंह ठाकुर का कहना है कि शासकीय जमीनों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण ज्यादा समय तक नहीं रहती है।

कानून व्यवस्था बनाए रखने फील्ड में दिखना चाहिए कार्य

राजनांदगांव। कलेक्टर डोमन सिंह ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कानून व्यवस्था के संबंध में राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री सिंह ने सभी अधिकारियों को शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अवैध अतिक्रमण, जुआ, सट्टा, चखना दुकान एवं अन्य अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फील्ड में कार्य दिखना चाहिए। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समन्वित तरीके से सभी अधिकारी कार्य करेंगे। प्रभावी ढंग से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण नियमों का पालन करते हुए हटाए। टीम एक साथ संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन फील्ड में कानून व्यवस्था बनाएं रखने के लिए अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई जारी रखें।

अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर 35 से भी ज्यादा अवैध व्यापार

रिसाली। लंबे समय से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर व्यापार करने वालों को खदेड़ा गया। नगर पालिक निगम रिसाली के आयुक्त आशीष देवांगन के निर्देश पर अस्थाई दुकानों को जेसीबी से हटाया गया। ऐसे दुकानों की संख्या लगभग 35 है।

नगर पालिक निगम रिसाली क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन बेदखली कार्रवाई की गई। निगम प्रशासन की टीम ने नेवई थाना परिसर स्थित पेट्रोल पंप से लेकर रेलवे क्रासिंग तक लगभग 35 अस्थाई दुकान हटाकर सरकारी जमीन को मुक्त कराया। फुटकर व्यापारियों ने बांस बल्ली और हाथ ठेले को बेस बनाकर पक्का निर्माण किया था। अधिकारियों ने पहले समझाईश दी।

असर नहीं होने पर तोड़ू दस्ता में शामिल सदस्यों ने बांस बल्ली को जब्त किया। इस कार्रवाई में प्रभारी भवन अधिकारी अखिलेश गुप्ता, राजस्व विभाग प्रभारी संजय वर्मा, प्रभारी सहायक अभियंता गोपाल सिन्हा, जगरनाथ कुशवाहा और स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी अधिकारी बृजेन्द्र परिहार आदि शामिल थे।

आचार संहिता खत्म होते ही निगम प्रशासन ने पहले देशी शराब दुकान जोरातराई परिसर में संचालित चखना सेंटर को ढहाया। निगम प्रशासन द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद भी टपरी नुमा दुकान नहीं हटाने पर बांस बल्ली को हटाया गया। इसी तरह सरस्वती कुंज के निकट डिस्पोजल गिलास और पानी पाऊच का अवैध कारोबार करने वालों पर कार्रवाई की। निगम आयुक्त आशीष देवांगन ने स्पष्ट निर्देश दिए है कि अतिक्रमणकारियों के साथ निगम कर्मी सख्ती के साथ पेश आए। प्रतिदिन तोड़ू दस्ता शहर का भ्रमण कर कार्रवाई करें।

विधायक के ईशारे पर हुई थी अजय पर जिला बदर की कार्रवाई!

बीजापुर। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजापुर में भाजपा-कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई है। पहले पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने कलेक्टर बीजापुर राजेंद्र कटारा पर पक्षपात पूर्ण चुनाव कराने का आरोप लगाया। इस पर पलटवार करते विधायक विक्रम मंडावी ने गागड़ा के बयान को बौखलाहट बताया। जुबानी जंग यहीं नहीं थमी, एक दिन पहले सोशल मीडिया पर कलेक्टर बीजापुर को लेकर पूर्व मंत्री गागड़ा ने पुन: निशाना साधा, जबाव में विधायक विक्रम ने भी सोशल मीडिया पर पलटवार किया। महेश-विक्रम में छिड़ी जुबानी जंग के बीच आज कांग्रेसी नेता पालिका उपाध्यक्ष पुरषोत्तम सल्लूर के एक बयान ने नई बहस को जन्म दे दिया है। सल्लूर ने अपने फेसबुक लाइव के दौरान यह कह दिया कि अजय पर जिलाबदर विधायक विक्रम के ईशारे पर हुआ था।

सीतापुर से जीते विधायक टोप्पो का तल्ख अंदाज, अफसरों को दी नसीहत

अंबिकापुर/सीतापुर। जीत के बाद बाद लगातार बीजेपी के विजयी प्रत्याशी राम कुमार टोप्पो अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। गुरुवार को रामकुमार टोप्पो अपने स्कूल पहुंचे थे शुक्रवार को उन्होंने क्षेत्र के अधिकारियों को कर्मचारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि, क्षेत्र का विकास उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल है। बैठक शुरू होने से पहले रामकुमार टोप्पो ने अपना परिचय दिया और अधिकारियों कर्मचारियों से भी उनका परिचय मांगा। पहल का स्वागत करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी अपनी दिक्कतों को लेकर उन्हें अवगत कराया। बैठक में एसडीएम भी मौके पर मौजूद रहे।

स्थानीय समस्याओं पर चर्चा करते हुए टोप्पो ने कहा कि हमें लोगों की परेशानी दूर करनी होगी। अगर हम और आप मिलकर जमीनी स्तर पर काम करें तो एक भी ऐसी समस्या नहीं होगी जिसे हम दूर नहीं कर पाएं। टोप्पो ने कहा कि जनता ने मुझे विकास के लिए चुनकर भेजा है और आपको सरकार ने यहां के विकास के लिए रखा है। हमें मिलकर किसानों और गरीबों की समस्या का अंत करना है। बीजेपी के विजयी प्रत्याशी रामकुमार टोप्पो ने कहा कि किसी के भी दबाव में काम करने की जरूरत नहीं है। जो सही और न्यायसंगत बात हो वहीं काम आप करें। किसी के बहकावे में भी नहीं आएं। आप बेहतर काम करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। उनकी की बातों को सुनकर अफसरों और कर्मचारियों में भी काम को लेकर उर्जा नजर आई। उन्होंने जीत के बाद कहा कि, क्षेत्र का विकास करना उनकी प्राथमिकता में शामिल है।

छत्तीसगढ़ में हार पर सिंहदेव ने कही जवाबदारी लेने की बात

दिल्ली/रायपुर। छत्तीसगढ़ में हार पर मचे हाहाकार के बीच दिल्ली के दस अकबर रोड पर कांग्रेस मंथन कर रही है। दिल्ली पहुंचे टीएस सिंहदेव ने कहा कि हार की जिम्मेदारी बूथ स्तर से लेकर सीएम तक की है और सबको इसकी जवाबदारी लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को दिल्ली रवाना होने से पहले कहा था कि हार को लेकर किसने क्या कहा मुझे कुछ मालूम नहीं है।

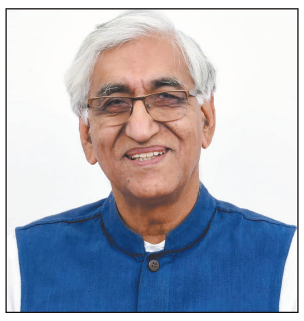

विधानसभा चुनाव 2023 को 2024 के लोकसभा चुनावों का सेमाफाइनल माना जा रहा था। जिसे लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन इन चुनावों में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार में बैठी कांग्रेस चुनाव हार गई। जिससे आगामी 2024 के चुनावों में हिंदी बेल्ट में कांग्रेस की वापसी मुश्किल हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश को छोड़ दे तो कांग्रेस पूरे उत्तर भारत में और कही नहीं है।

साल 2023 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 35 सीटें मिली जबकि भाजपा को 54 सीटें मिली। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 66 सीटें मिली जबकि बीजेपी ने 163 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की। राजस्थान में कांग्रेस को 69 और भाजपा को 115 सीटें मिली। इन सबसे अलग तेलंगाना में कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन रहा। कांग्रेस ने तेलंगाना में 119 सीटों में से 64 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया और बीआरएस को 39 सीटें मिली। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) 2014 में राज्य गठन के बाद पहली बार तेलंगाना में अपनी सरकार बनाई।

पूर्व कांग्रेस विधायक ने लगाया सैलजा व सिंहदेव पर गंभीर आरोप

पराजय के बाद कांग्रेस नेताओं का भड़ास अब सामने आने लगा है। सरगुजा इलाके में कांग्रेस का सुफड़ा साफ हो जाने के बाद पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह रायपुर पहुंचे और सीधा आरोप लगाया कि प्रदेश प्रभारी सैलजा बड़े नेताओं के हाथों

बिक गई थीं। भाजपा को सत्ता में लाने का पूरा श्रेय उप मुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव को जाता है। मै तो मांग करता हूं कि सिंहदेव को राज्यपाल बनाकर उपकृत किया जाना चाहिए।

सिंह यहीं नहीं रूके बल्कि आगे कहा छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं पर घमंड सिर चढकर बोल रहा था। कांग्रेस जिस पीएम को घेर रही थी, डिप्टी सीएम मंच से उनके लिए कह रहे थे, मोदीजी अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे में जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता कैसे समर्थन करेंगे। पूरी पार्टी कहती रही कि हमने 36 वादे पूरे किए, और डिप्टी सीएम बार-बार दोहराते रहे कि 12 वादे पूरे किए गए हैं। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा टी. एस. सिंहदेव को पूर्णकालिक सीएम बनाते तो कांग्रेस की वही हालत होती जो पांच वर्ष पूर्व रमन सरकार की वजह से भाजपा की हुई, हम 15 में सिमट जाते।संगठन का कामकाज पूरी तरह से पटरी से उतर चुका था, बृहस्पत सिंह ने सैलजा पर सीधा आरोप लगाया कि प्रदेश प्रभारी टिकट वितरण के मामले में बिक चुकी थी। इसके पहले के प्रभारियों ने बहुत अच्छा काम किया था। मेरी राहुल जी से आग्रह है, मिलकर भी कहूंगा कि तत्काल प्रभारी को बदला जाए। तभी डैमेज कंट्रोल हो पाएगा।

विधानसभा चुनाव प्रचार में रास्ते से कैसे भटकी कांग्रेस ?

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे काफी आश्चर्यचकित रहे। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के साथ ही शायद कई आम लोगों के लिए भी ये चुनाव हैरान करने वाला साबित हुआ। इस चुनाव में भाजपा ने छत्तीसगढ़ में 15 साल के बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस को एक झटके में हरा दिया और सत्तासीन हो गई। चुनाव नतीजों तक भूपेश सरकार ने एक बार भी ये सोचा नहीं होगा कि 3 दिसंबर का दिन कांग्रेस के लिए काफी भारी पड़ सकता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की दोबारा वापसी को लेकर कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट थी या यू कहें कि ओवर कॉन्फिडेंस में थी। कांग्रेस ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत पर किसानों को केंद्रित किया। धान खरीदी की गारंटी के वादे और किसान न्याय योजना को लेकर लोगों के बीच गई। बाद में कांग्रेस ने महिलाओं पर फोकस किया। इस बीच युवाओं को भी साधने कोर कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद कांग्रेस ने अपने चुनाव अभियान में ओबीसी और जातीय जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठाया। लेकिन 3 नवंबर को ईडी ने भूपेश बघेल पर कैश कूरियर के हवाले से ये आरोप लगाया कि महादेव सट्टेबाजी एप प्रमोटर्स ने तत्कालीन सीएम को चुनावी खर्चे के लिए 508 करोड़ रुपये भिजवाएं हैं। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव होना था, लेकिन उससे तीन दिन पहले भूपेश बघेल पर लगा इस आरोप ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रचार अभियान की दिशा ही बदल दी। इन आरोपों के बाद कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभियान धीमा पड़ गया। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अपना चुनाव प्रचार कांग्रेस के भ्रष्टाचार के साथ शुरू किया। जिसमें मुख्य रूप से शराब घोटाला, कोयला घोटाला और गोबर घोटाला को शामिल किया गया। इसके बाद भाजपा ने अपना मेनिफेस्टो जारी किया। जिसे छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी के नाम से जनता के बीच रखा। लेकिन भूपेश बघेल पर ईडी की तरफ से लगाए 508 करोड़ की रिश्वत के आरोपों के बाद भाजपा ने इस मुद्दे को अपने चुनाव प्रचार अभियान में जमकर भुनाया।

संक्षिप्त समाचार

जयसिंह अग्रवाल का निवास होगा पूर्व मुख्यमंत्री बघेल का आवास

रायपुर। शंकर नगर स्थित पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का बंगला अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नया निवास होगा।पारिवारिक सदस्यों ने वास्तुनुसार इस बंगले का चयन किया है। उल्लेखनीय है कि नियमानुसार सत्ता परिवर्तन के मंत्रियों को शासकीय आवास खाली करना होता है मुख्यमंत्री निवास से सूत्रों के मुताबिक भूपेश बघेल के सभी रिश्तेदारों ने जयसिंह अग्रवाल के बंगले का चयन भूपेश बघेल के लिए पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से रहने के लिए किया है। बताया जाता है कि अगले सप्ताह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना निवास छोड़कर जयसिंह अग्रवाल के बंगले में रहने आ जाएंगे। भूपेश बघेल के परिवारजनों ने वास्तु के अनुसार बंगले का चयन किया है इस बंगले के अलावा स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव के बंगले को जांचा-परखा गया लेकिन वास्तु के हिसाब से जयसिंह अग्रवाल का बंगला उन्हें उपयुक्त लगा। पहले पूर्व मुख्यमंत्री के बंगले की साफ-सफाई रंग-रोगन के बाद मुख्यमंत्री आवास को नये मुख्यमंत्री के लिये तैयार किया जायेगा।

अलसुबह कालीबाड़ी चौक पर हुई अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई

रायपुर। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने आज सुबह कालीबाड़ी चौक पर लगभग 10 साल पुराने अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई की। निगम के अतिक्रमण तोड़ू दस्ते में शासकीय वन आवासीय परिसर से लगी लगभग साढ़े चार सौ वर्गफीट जमीन को पुराने अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। लगभग दस साल से इस जमीन पर किसी ज्योतिप्रकाश ने अवैध रूप से अपना कब्जा किया था और उस पर चार पक्की दुकानें बनाकर व्यावसायिक परिसर चला रहा था। नगर निगम जोन क्रमांक 3 के आयुक्त श्री राकेश शर्मा ने बताया कि इस अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए कब्जाधारी को 2017 में भी नोटिस जारी की गई थी। कब्जाधारी ने साढ़े चार सौ वर्गफीट इस जमीन को अपने स्वामित्व की भूमि बताकर कब्जा हटाने से मना किया था। इस पर राजस्व अम्ले ने तहसीलदार के नेतृत्व में मामले की जांच की थी और इस भूमि को शासकीय नजूल की भूमि होना पाया था। इसके बाद आज सुबह निगम के अतिक्रमण तोड़ू दस्ते ने राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति में इस अवैध अतिक्रमण को ढहा दिया है और जमीन को मुक्त करा लिया है।

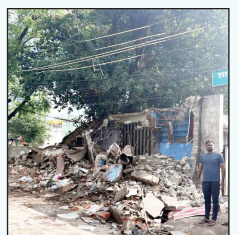

अंताक्षरी में चंचल, खुशबू, तृप्ति व दुलेश्वरी रही प्रथम

रायपुर। गुरुकुल महिला महाविद्यालय

वार्षिकोत्सव खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान शुक्रवार को रंग मंदिर में अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें चंचल पटेल, खुशबू वर्मा, तृप्ति चौहान व दुलेश्वरी रघुवंशी प्रथम रही। जबकि प्राची साहू, भूमिका साहू, भूमिका साहू व कंचन देवांगन उपविजेता चुनी गई। शनिवार को समूह व युगल नृत्य प्रतियोगिता होगी। अंताक्षरी प्रतियोगिता को चार समूह में बांटा गया था जिसमें सुर, लय, ताल और धुन थे। अंताक्षरी प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और प्रतियोगिता 6 अलग-अलग राउंड में संपन्न हुआ। रैपिड फायर, चेहरे पर चेहरा और वीडियो क्लिपिंग दिखाकर प्रतिभागियों को गाना पहचाने के लिए कहा गया! इस प्रतियोगिता में सूर टीम विजेता रहे तथा धूम टीम उपविजेता रही। डॉ राजेश अग्रवाल ,प्रीति साहू, वर्षा सोनी पूनम गोस्वामी प्राध्यापकों के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ।

कांग्रेस की हार पर राजेश मूणत का बड़ा बयान, कहा-

जनता को भय और आतंकवाद से मुक्ति चाहिए था, इसलिए भाजपा को चुना

रायपुर। भाजपा नेता राजेश मूणत ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गिरोह बनाकर भ्रष्टाचार के लिए काम कर रही थी, जनहित में काम नहीं की। अगर काम करती तो सरगुजा से लेकर बस्तर की सीटों में एकतरफा निर्णय नहीं आता। जनता को भय और आतंकवाद से मुक्ति चाहिए था, इसलिए भाजपा को चुना।

पूर्व मंत्री और रायपुर पश्चिम से नवनिर्वाचित विधायक राजेश मूणत ने अवैध कब्जा हटाने को लेकर कहा कि जिन लोगों ने अवैध कब्जा बसाया था, वही उजड़ रहे हैं। प्रशासन यह चिन्हित करें कि कब्जाधारी कौन हैं। उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही थी यह अधिकारी बताएं। जिन अधिकारियों ने गड़बड़ की है। उन पर तो निश्चित ही गाज गिरेगी। मूणत ने कहा कि 15 साल के

मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह को सरकारी बंगला देने में देरी कर दी। तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी मंडल ने बंगला अलॉटमेंट करने की बात कही, लेकिन कांग्रेस सरकार ने महीनों तक बंगला नहीं दिया। जो बंगला दिया वह थर्ड क्लास का था। मंत्रियों को सुरक्षा देने से भी मना कर दिया, लेकिन अभी मुख्यमंत्री को बंगला अलॉट कर दिया गया है।

उन्होंने सवाल किया कि सरकार गठन से पहले कैसे बंगला अलॉट कर दिए गए। अफसर सुधर जाएं, क्योंकि अभी भी कई अधिकारी कांग्रेस के समर्थन में काम कर रही है। मूणत ने विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को लेकर कहा कि संगठन की अपनी प्रक्रिया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का गठन होगा। मुख्यमंत्री बीजेपी का ही कोई कार्यकर्ता बनेगा। छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर कांग्रेस द्वारा बीजेपी पर लगाए आरोप पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी दिल और दिमाग में है। कांग्रेस के जैसे नहीं है। कांग्रेस अपनी पार्टी की चिंता करें, उनके एक मंत्री कहते है अपने-अपने बंटवारे में लगे रहे। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ईवीएम में ऐसा हुआ। हमें मिर्ची नहीं लगती। उन्होंने कहा कि अल्बर्ट पिंटू को गुस्सा क्यों आता है? जनता ने वोट दिया है, समीक्षा करो। कांग्रेस जनहित में काम नहीं करती है। अगर की होती तो रायपुर की सातों सीट और सरगुजा बस्तर में एक तरफा जीत हमें नहीं मिलती। जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। जनता को भय और आतंकवाद से मुक्ति चाहिए थी।

रायपुर पश्चिम में अस्त हुआ 'कांग्रेस का सूरज', अपने वार्ड में भी लोगों ने नकारा

रायपुर। पिछले विधानसभा चुनाव में कद्दावर मंत्री राजेश मूणत को हराकर पश्चिम के तत्कालीन प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने अपना परचम लहराया था। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में पश्चिम में कांग्रेस का सूरज यानी विकास उपाध्याय मानो अस्त हो गया। हार की रिकार्ड का आलम ये है कि विकास को अपने वार्ड के लोगों ने भी पूरी तरह नकार दिया।

यही कारण है कि रायपुर विधानसभा के चारों सीटों में रायपुर पश्चिम ही एक मात्र ऐसी सीट है जहां एक भी वार्ड में कांग्रेस के प्रत्याशी विकास उपाध्याय को बहुमत नहीं मिला। बता दें कि रायपुर पश्चिम में कुल 21 वार्ड आते है, जहां सभी वार्डों में उन्हें हार मिली है। उन्हें मिली इस हार का अब कांग्रेस नेताओं ने हार की समीक्षा करनी शुरू कर दी है। बता दें कि विकास 41 हजार से ज्यादा वोटों से ये चुनाव हारे है।

रायपुर पश्चिम विधानसभा सीट में 6 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां विकास उपाध्याय दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। इसमें 19 कोटा में उन्हें 91 तो भाजपा प्रत्याशी राजेश मूणत को 332 वोट मिले। 76 गुढ़ियारी में 87, 90 गुढ़ियारी में 94, 138 रामसागरपारा में 88, 181 कॉलेज वार्ड में 84, और 226 डगनिया में भी सिर्फ 71 वोट विकास को मिले, जबकि मूणत को क्रमश 178, 285, 307, 411, और 115 है। हैरानी की बात ये है कि 19 के 19 राउंड में किसी में भी उन्होंने लीड नहीं मिली। कुल मिलाकर विकास उपाध्याय 41 हजार 229 वोटों से उन्हें हार मिली है।

राजधानी रायपुर के दक्षिण विधानसभा सीट की बात करें तो यहां भाजपा के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल ने जीत का रिकार्ड बनाया है। बृजमोहन को 20 वार्डों में से 18 में बढ़त मिली। उत्तर की बात करें तो यहां भाजपा प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा को 18 में से 14 वार्डों में बढ़त मिली। वहीं रायपुर ग्रामीण में भी मोतीलाल साहू ने सभी वार्डों में अच्छी सफलता अर्जित की।

कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, सभी का नाम चर्चा में

छत्तीसगढ़ में सीएम फाइनल नहीं, विधायक दल से रायशुमारी करके पर्यवेक्षक लेंगे फैसला : रमन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सीएम के चुनाव को लेकर बीजेपी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। जिसमें केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनेवाल, अर्जुन मुंडा और राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम छत्तीसगढ़ आएंगे। ये तीनों ही नेता नवनिर्वाचित विधायकों से रायशुमारी करने के बाद दिल्ली प्रस्थान करेंगे।जहां पर केंद्रीय समिति के सामने सीएम पद का नाम ऐलान होगा।

वहीं बीजेपी से सीएम फेस को लेकर लेकर डॉ रमन ने कहा कि अभी किसी का भी नाम फाइनल नहीं हुआ है। जब तक राय मशविरा नहीं होगा। तब तक कहना मुश्किल है, अभी सभी नाम चर्चा में है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर सरकार गठन किए जाने के सवाल पर डॉ रमन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में

पिछली बार से बेहतर रिजल्ट आएंगे। 11 की 11 सीटें जीतेंगे, इस बड़े लक्ष्य को लेकर सरकार का गठन किया जा रहा है।

ईवीएम गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस पर पलटवार

वहीं कांग्रेस के कई नेता छत्तीसगढ़ में मिली करारी हार की वजह ईवीएम को मान रहे हैं।जिसमें सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हैं। ईवीएम पर भूपेश बघेल के बयान पर डॉ रमन ने पलटवार किया है। रमन सिंह ने कहा कि जहां कांग्रेस जीतती है। वहां चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं होती। जहां कांग्रेस पीट जाती है। वहां इन्हें शंका, कुशंका होने लगती है। बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं, बीजेपी निष्पक्ष है। नई तकनीकी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ईवीएम से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यह हार का बहाना ढूंढते हैं। बीजेपी कभी हार और जीत में कारण नहीं ढूंढती है।

इसके अलावा रमन सिंह ने बीजेपी के पोस्टर में छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर ना होने पर भी बयान दिया है। रमन सिंह ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति सम्मान राजनीतिक पार्टी की सीमा से हटकर है। छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में छत्तीसगढ़ महतारी का स्थान है।

राज्यपाल ने षष्टम विधानसभा गठन की जारी की अधिसूचना

पूर्व विधायकों को बंगला खाली करने का नोटिस

रायपुर। छत्तीसगढ़ की पांचवी विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद 2018 में निर्वाचित सभी विधायकों की सदस्यता भी समाप्त हो गई है।इनमें से जो प्रत्याशी चुनाव नहीं जीते या फिर उन्हें मौका नहीं मिला।वे सभी पूर्व विधायक बन चुके हैं।जिसके बाद अब विधानसभा सचिवालय ने हारने वाले सभी विधायकों को आवास खाली करने के निर्देश जारी किए हैं। जिसके बाद दिसंबर माह से किसी भी पूर्व विधायक को आवास का भत्ता नहीं दिया जाएगा।

आपको बता दें कि गुरुवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 90 सदस्यीय विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों की सूची राज्यपाल बिस्वभूषण हरिचंदन को सौंपी है।जिसके बाद राज्यपाल ने छठवीं विधानसभा गठन की अधिसूचना जारी कर दी।

सीएम समेत सभी मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर

आपको बता दें कि राज्यपाल ने इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीन दिसंबर को परिणाम आने के बाद अपना और अपने मंत्रिमंडल सदस्यों का इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा था।

राज्यपाल ने इस्तीफा मंजूर करते हुए बघेल को नई सरकार के गठन तक कार्यभार संभालने के लिए कहा था। भूपेश बघेल और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के त्याग पत्र के संबंध में दो अधिसूचना जारी की गई है। पहली अधिसूचना राजभवन की तरफ से राजभवन के सचिव के हस्ताक्षर से जारी हुई है,वहीं दूसरी अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) की तरफ से मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से जारी की।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता अमरजीत भगत ने नहीं मुंडवाई मूंछ, सिर्फ कैंची चली

■ कब कटेगी मूंछ!

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी हार मिली है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 90 सीटों में 68 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी लेकिन इस बार 35 पर ही सिमट गई। भाजपा 54 में जीत हासिल कर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। वहीं चुनाव जंग के बीच भूपेश सरकार में मंत्री रहे अमरजीत भगत ने एक बयान दिया था कि अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी तो वह अपनी मूंछ मुंडवा लेंगे। बीजेपी के जीत के बाद भाजपा नेता लगातार उन्हें मूंछ मुड़वाने की बात याद दिला रहे हैं। इस बीच आज अमरजीत भगत ने मूंछ पर कैंची चलवाते हुए बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अपनी मूंछ कटवाने वाले बयान पर कायम हूं। प्रधानमंत्री मोदी को पहले अपना वादा पूरा करना चाहिए।

अमरजीत भगत ने बाल और मूंछ कटवाते हुए कहा कि सरकार बनाने के लिए और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा लाने के लिए इस तरह की बात होते रहती है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत अपनी मूंछ कटाने वाले बयान

पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को पहले अपना वादा पूरा करना चाहिए। उन्होंने नोटबंदी के दौरान कहा था कि 50 दिन में अगर मेरा निर्णय गलत हो गया तो मुझे किसी भी चौराहे पर लटका देना। मैं अभी भी अपने बयान पर कायम हूं। इससे पहले की भाजपा के नेता इस पर कुछ कहें। सरकार नहीं बनने का दुख है। जनता के चूक कर दिया। यहां के कृषि की अर्थव्यवस्था जो यही से बढ़ रही वो अब पीछे जा रही है।

चुनाव के दौरान हर मंचों पर बीजेपी के नेता छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो लगाते थे। छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो पोस्टरों में फोटो नहीं दिख रहा वाले सवाल पर अमरजीत भगत ने कहा कि ये तो शुरुआत है आगे क्या क्या होता है देखिए। जिसका काम हो जाता है उसकी चर्चा नहीं ये लोग नहीं करते। पहले फोटो का उपयोग करते थे अब वो दिखाई नहीं दे रहा।

मुख्यमंत्री पद को लेकर हो रही लेटलतीफी पर अमरजीत भगत ने कहा कि उनके दल की बात है। मैं आदिवासी होने के नाते चाहता हूं किसी आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए। सरगुजा और बस्तर ने खूब समर्थन किया ये भी आदिवासियों का समर्थन करें।

बुलडोजर से हो रही कार्रवाई पर अमरजीत भगत ने कहा कि ये तो हर सरकार की प्राथमिकता और काम करने का शैली होता है। सरकार गठन से पहले लोगों के ठेले और आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। एक डर पैदा करने की शुरुआत है जिन पर कार्रवाई हो रही उनको नोटिस देना चाहिए, उनका व्यवस्थापन होना चाहिए।

पूर्व मंत्री भगत को मूंछ मुंडवाने का वादा पूरा करने भेजा गया स्पीड पोस्ट से शेविंग किट

राजनांदगांव। जिले के पूर्व प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत को राज्य में भाजपा सरकार बनने पर मूंछ मुंडवाने का वादा याद दिलाने भाजयुमो ने शुक्रवार को स्थानीय पोस्ट ऑफिस से उनके निवास में शेविंग किट का एक बॉक्स भेजा है। उल्लेखनीय हैं कि चुनाव पूर्व भगत ने ताल ठोंकते हुए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के पुन- सत्तासीन होने का दावा करते कहा था कि भाजपा की सरकार बनने पर वह अपना मूंछ मुंडवा देंगे। मीडिया के सामने उन्होंने इस बयान के जरिये भाजपा को खुली चुनौती दी थी। भाजपा की सरकार बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। भाजयुमो के जिलाध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने पोस्ट ऑफिस में पहुंचकर एक शेविंग किट का बॉक्स भगत के पैतृक निवास के लिए स्पीड पोस्ट किया है। चुनाव के दौरान पूर्व प्रभारी मंत्री ने कड़वे वचन बोले थे जिसमें उन्होंने मूंछ मुंडवाने का दावा किया था। अब वक्त आ गया है कि भगत अपना वादा पूरा करें। यदि उन्हें मूंछ मुंडवाने के लिए नाई नहीं मिल रहा है तो भाजयुमो यह व्यवस्था भी कर सकता है। इस दौरान मोनू बहादुर, गोलू सूर्यवंशी, आशीष जैन, गोलू गुप्ता, सज्जन ठाकुर, प्रखर श्रीवास्तव समेत अन्य लोग शामिल थे।

उत्तर-दक्षिण की जंग कितनी जायज

उमेश चतुर्वेदी

अव्वल तो भाजपा से हार के बाद कांग्रेस और विपक्ष को इस बात की मीमांसा करनी चाहिए कि उससे कहां रणनीतिक चूक हुई, पर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता हर हार के बाद विपक्ष अपनी तरह से एक नया नैरेटिव गढ़ लेता है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को सिर्फ तेलंगाना में मिली जीत के बाद कांग्रेस एक बार फिर नया नैरेटिव गढ़ रही है। वह यह नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश कर रही है कि विंध्य पर्वत से उत्तरी इलाके के लोगों की सोच सांप्रदायिकता और जातिवाद के इर्द-गिर्द ही घूमती है, जबकि दक्षिण के लोग राजनीतिक रूप से कहीं ज्यादा सचेत, प्रगतिशील और परिपक्व हैं। वह यह जताने की कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी की सोच वक्त से आगे की है। चूंकि दक्षिण के लोगों की सोच ज्यादा परिपक्व है, इसलिए वे राहुल की बातों पर भरोसा कर रहे हैं। पहले कर्नाटक और फिर तेलंगाना की जीत इसका परिचायक है। नैरेटिव के बहाने उत्तर बनाम दक्षिण की जंग का लंबा इतिहास रहा है। कहा जाता रहा है कि विंध्य के उत्तर वाले लोग विदेशी धरती से आए आर्य की संतान हैं, जबकि विंध्य के दक्षिण वाले लोग बुनियादी रूप से भारत के ही लोग हैं। हालांकि दयानंद सरस्वती जैसे लोग इसका विरोध करते रहे। आज के दौर के राजनेता सुब्रमण्यम स्वामी हों या फिर मानवशास्त्री, सबका मानना है कि चाहे उत्तर के लोग हों या दक्षिण के, वे बुनियादी रूप से एक ही हैं। शंकराचार्य ने पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में पीठ स्थापित करके इस विभाजनकारी सोच पर रोक लगाने की कोशिश की थी। भारत सरकार अधिनियम के तहत जब 1937 में राज्यों में चुनाव हुए, तब से पेरियार की अगुआई में शुरू हुआ हिंदी विरोध भी उत्तर बनाम दक्षिण की ही जंग का विस्तार था। जब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी राष्ट्रपति नहीं बन पाए, तब भी उत्तर बनाम दक्षिण की वैचारिक जंग को हवा दी गई। संविधान सभा की मंजूरी के बावजूद हिंदी अगर देश की व्यावहारिक रूप से राजभाषा नहीं बन पाई, तो इसके पीछे भी उत्तर बनाम दक्षिण वाली सोच ही थी। उत्तर के राज्यों की गरीबी व पलायन और दक्षिण के आर्थिक उत्थान के पैमाने पर भी यह जंग चलती रही है। वैसे भी देश को बांटने और किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को हंसी का पात्र बनाने की परंपरा लंबे समय से है। पर सोच के स्तर पर उत्तर और दक्षिण के राज्यों को बांटने की मौजूदा कोशिश बाकी कोशिशों से अलग है। स्वाधीनता आंदोलन की कोख से निकली कांग्रेस ने अंदरूनी राजनीति के चलते भले ही कभी ऐसी राजनीति को हवा दी हो, पर उसने खुलकर कभी ऐसी विभाजनकारी सोच को हवा नहीं दी। कांग्रेस की संस्कृति और राजनीतिक परंपरा भारत को जोड़ने की रही है, तोड़ने की नहीं। ताजिंदगी कांग्रेसवाद के विरोधी रहे समाजवादी नेता मधु लिमये ने अपने आखिरी लेख में कांग्रेस को देश की एकता का प्रतीक बताया था। पर लगता है कि कांग्रेस के आज के कर्णधार और उनके सलाहकारों को कांग्रेस की इस प्रकृति की जानकारी नहीं है। एक बारगी मान भी लें कि कांग्रेस का नैरेटिव सही है, कि दक्षिण के लोग उत्तर के लोगों के मुकाबले राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं, तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि आपातकाल सही था, क्योंकि उसके बाद हुए आम चुनावों में कांग्रेस को जो 154 लोकसभा सीटें मिली थीं, उनमें से 89 सीटें दक्षिण भारत में ही मिली थीं। उत्तर में सिर्फ मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट पर उसे जीत मिली थी। निश्चित तौर पर कांग्रेस भी इसे स्वीकार नहीं करेगी। तो फिर वह उत्तर बनाम दक्षिण को लेकर ऐसा नैरेटिव क्यों फैला रही है? तमिलनाडु में कांग्रेस 1971 के विधानसभा चुनावों से ही गायब है। अगर वह कभी दिखती है, तो द्रमुक या अन्नाद्रमुक के सहारे। केरल और आंध्र प्रदेश की सत्ता से भी कांग्रेस दो चुनावों से दूर है, तो क्या यह मान लिया जाए कि इन प्रदेशों के लोगों की सोच छोटी है। आज के दौर में हर राजनीतिक दल राजनीतिक फायदे के लिए नैरेटिव गढ़ सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे देखना होगा कि उससे देश का मानस न बंटे। राजनीतिक दलों को चाहिए कि वह विभाजन की सोच पर लगाम लगाए, क्योंकि इसका खामियाजा समूचे देश को भुगतना पड़ेगा। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कांग्रेस को इससे परहेज करना चाहिए।

नतीजों में छिपा लोकसभा चुनाव का नरेटिव

अजय बोकिल

देश में लोकसभा चुनाव से पांच महीने पहले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में हिंदी पट्टी में भाजपा की जबर्दस्त जीत केवल मोदी की लोकप्रियता की कायमी पर मोहर ही नहीं है, इसने आगामी लोकसभा चुनाव का नरेटिव भी सेट कर दिया है। ये है मोदी की गारंटी और मोदी का नया जातिवाद। दरअसल, ये कांग्रेस की चुनावी गारंटियों और क्षेत्रीय दलों के जातिवाद के मुद्दों का नया जवाब है। इन तीनों हिंदी भाषी राज्यों में से दो में सत्तारूढ़ और एक में सत्ताकांक्षी कांग्रेस की करारी हार में छिपा सबक यह भी है कि अगर उसे राष्ट्रीय पार्टी बने रहना है तो उसे क्षेत्रीय दलों के मुद्दों की पिच पर बैटिंग करना छोड़कर खुद को अखिल भारतीय सोच के साथ ही मतदाता के पास जाना होगा। दूसरे, चुनाव प्रबंधन की परीक्षा में कांग्रेस को माइक्रो मैनेजमेंट के पेपर में प्रथम श्रेणी के अंक लाने होंगे। इन नतीजों ने यह भी साबित किया कि लोकतंत्र में चुनाव केवल परसेप्शन, सोशल मीडिया एक्टिवनेस और प्रायोजित सर्वे के भरोसे नहीं जीते जाते। जनमानस को भांपने और जनाकांक्षा को संतुष्ट कर सकने के काम और वादों को पूरा करने से जीते जाते हैं।

पांच राज्यों में से राजस्थान को हम इस आधार पर अलग रख सकते हैं कि वहां बीते 30 सालों से हर पांच साल बाद सत्ता बदलने का रिवाज है। लेकिन इस रिवाज में भी इस बार नई बात भाजपा को स्पष्ट बहुमत का मिलना है, वरना वहां ज्यादातर समय सरकारें बहुत किनारे के बहुमत के साथ बनती रही है और उसे टिकाने के लिए मुख्यमंत्रियों को गहलोत की तरह 'जादूगरी' दिखानी पड़ती रही है। लेकिन राजनीति शास्त्र के हिसाब से मप्र और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम वाकई अध्ययन करने लायक हैं। दरअसल, भाजपा ने बरसों की एंटी इनकम्बेंसी को प्रो- इनकम्बेंसी में बदला तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार, जिसे ज्यादातर लोग अजेय मानकर चल रहे थे, को भाजपा ने बिना किसी चेहरे को प्रोजेक्ट किए और आरंभिक हिचक के बाद चुनाव अभियान को तेज करके सत्ता से दमदार तरीके से बेदखल किया। यहां हमे भाजपा और कांग्रेस की चुनाव रणनीति और प्रबंधन के फर्क को समझना जरूरी है।

कांग्रेस आला कमान ने तीनो राज्यों में क्षेत्रीय क्षत्रपों पर भरोसा किया, जबकि भाजपा ने मोदी का चेहरा आगे कर विधानसभा के साथ-साथ आगामी लोकसभा चुनाव में भी

मोदी की लोकप्रियता की सफल प्री टेस्टिंग कर ली। यह भाजपा में क्षत्रप संस्कृति के समापन का समारोही ऐलान भी था। बेशक मप्र की जीत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अहम भूमिका रही है। उन्हें राज्य में पांचवीं बार सीएम प्रोजेक्ट भले न किया गया हो, लेकिन उन्होंने इसे भी अपनी ताकत बनाकर अपने और प्रकारांतर से भाजपा के पक्ष में लहर में तब्दील करने में जबर्दस्त कामयाबी हासिल कर ली। पार्टी को उन्हें अनदेखा करना आसान नहीं होगा। दूसरे, मप्र में शिवराज सरकार के खिलाफ जबर्दस्त और परिवर्तनकारी एंटी इनकम्बेंसी है, यह परसेप्शन कैसे बना और किसने बनवाया? यह व्यक्तिगत पसंद और नापसंद पर आधारित था, आम जनता का उससे खास लेना-देना नहीं था। अलबत्ता भाजपा कार्यकर्ताओं में असंतोष जरूर था। और इसी एंटी इनकम्बेंसी के अर्द्धसत्य आधारित परसेप्शन को 'ब्रह्मसत्य' मानकर कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति तैयार की, जिसका खोखलापन मप्र में मतदाता ने भाजपा को पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 8 फीसदी वोट ज्यादा देकर साबित कर दिया। लेकिन इन चुनावों का राजनीतिक नवनीत वो मुद्दे हैं, जिनको लेकर भाजपा और एनडीए गठबंधन अगले साल में अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव में जाना चाहेगा। पहला तो गारंटी है। इस देश में रेवड़ी कल्चर की शुरुआत दक्षिणी राज्य तमिलनाडु से हुई थी, जिसका उत्तर भारत में बीजारोपण आम आदमी पार्टी ने किया। इसका उसे खूब राजनीतिक लाभ भी मिला।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुरू में तो इस रेवड़ी कल्चर से देश को आगाह किया, लेकिन बाद में वो और उनकी पार्टी खुद इसी रंग में रंग गए। ऐसे में रेवड़ियों के बूते सत्ता का महल सजाने वाली पार्टियां, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, यह भूल गई कि रेवड़ियों की प्रतिस्पर्धा में भाजपा उन्हें मीलों पीछे छोड़ सकती है, क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज्यादा संसाधन उसी के पास है। मप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वही हुआ। कांग्रेस ने इस रेवड़ी कल्चर पर अपनी गारंटी का मुलम्मा चढ़ाया तो मोदी ने इसे ही अपनी गारंटी बताकर उसे राजनीतिक सिक्योरिटी बांड में तब्दील कर दिया। अगले लोकसभा चुनाव में यह बांड पूरी ताकत से बेचा जाएगा। इसमें दो राय नहीं कि हिंदू समाज और खासकर उत्तर पश्चिम भारत में मोदी के दीवानों की कमी नहीं है। यह दीवानगी समूचे पिछड़े वर्ग में तो है ही, सवर्णों में भी जबर्दस्त है। आंशिक रूप से मोदी दलित और आदिवासियों में भी कबूल हो चुके हैं। लोगों की यह मोदी भक्ति तर्कों और प्रश्नों से परे है। इसमें जल्द कोई कमी आएगी, यह मान लेना खुद को भ्रम में रखना है।

एक तरह से यह मान लिया गया है कि मोदी जी करिश्माई इंसान हैं। वो जो कहते हैं वो करते हैं। और वो वही करते हैं, जो बहुतांश हिंदू मन चाहता है। यह हकीकत है कि मोदी की इस गजब विश्वसनीयता पर विरोधियों द्वारा लगाए जाने वाले तमाम प्रश्नचिन्ह जनता ने खारिज कर दिए हैं। यानी कांग्रेस अथवा दूसरी विपक्षी पार्टियों की रेवड़ियों अथवा गारंटियों पर मोदी की गारंटी भारी पड़ी है और आगे भी भारी पड़ेगी। इसका असर उन दक्षिणी राज्यों में भी दिखेगा, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वहां भाजपा के लिए दरवाजे पहले ही नहीं खुले थे या फिर खुलने के बाद अब बंद हो गए हैं। यानी वहां विधानसभा चुनाव में मोदी का जादू भले न चला हो, लोकसभा में वो कुछ न कुछ असर जरूर दिखाएगा। एक और मुद्दा है मोदी का नया जातिवाद। देश में ओबीसी जातिगणना को लेकर मोदी सरकार पर बनाए जा रहे राजनीतिक दबाव और हिंदू एकता के बरक्स मंडल राजनीति की चिंगारी को फिर से हवा देने की सुनियोजित कोशिशों के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिंदू सहित सभी समाजों की चार नई जातियां गिनाना शुरू किया है।

ये हैं युवा, महिला, किसान और गरीब। इसे मंडल राजनीति-2 के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। समूचे देश में यह दांव कितना कारगर होगा, यह देखने की बात है, लेकिन तीन हिंदी भाषी राज्यों में तो यह कामयाब रहा है। मतदाता ने कांग्रेस के जातिगणना के वादे को खास तवज्जो नहीं दी। खासकर मप्र में ये मुद्दा इसलिए भी बेअसर रहा, क्योंकि यहां बीजेपी बीस साल से पिछड़ों की राजनीति ही कर रही है और अधिकांश पिछड़ी जातियां राष्ट्रीय स्तर पर मोदी को ही अपना आइकन मानती हैं और इसमें कोई फर्क शायद ही पड़े। यहां सवाल यह है कि इन परिस्थितियों में कांग्रेस को आखिर किस तरह की राजनीति करनी चाहिए और जाति गणना का मुद्दा उठाने से उसे क्या लाभ मिलना है? यह सवाल इसलिए भी अहम है, क्योंकि कांग्रेस में शीर्ष स्तर पर आज भी ओबीसी नेताओं की संख्या नगण्य है। वहां ज्यादातर अगड़े और गिने चुने दलित नेता ही हैं।

राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान जैसे जैसे ओबीसी का मुद्दा उठाना शुरू किया, कहते हैं कि वैसे वैसे कमलनाथ के मन में यह शंका घर करती गई कि यदि पार्टी सचमुच चुनाव जीती तो कहीं आला कमान ऐन वक्त पर किसी ओबीसी को सीएम न बना दे। ओबीसी राजनीति के प्रति अनावश्यक झुकाव कांग्रेस के लिए आत्मघाती ही होगा। दूसरा मुद्दा सनातन का रहा। हालांकि, सनातन धर्म पर हमला कांग्रेसनीत् इंडिया गठबंधन में शामिल डीएमके ने किया था, जो तमिलनाडु की राजनीति के हिसाब से सही भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ने उससे खुद को अलग नहीं किया। जबकि यह बहुसंख्य हिंदुओं की आस्था पर सीधी चोट थी। बीजेपी ने उत्तर भारत में इसी बिना पर कांग्रेस पर हमले किए कि वह सनातन धर्म विरोधी है।

कमलनाथ ने मप्र में इस खतरे को भांपकर खुद को ज्यादा सनातनी साबित करने की कोशिश की, लेकिन उस पर किसी ने भरोसा नहीं किया और भाजपा की इस पिच पर वो हिट विकेट ही हुए। इसी तरह इजराइल- हमास युद्ध का भारत और चुनाव वाले तीन राज्यों से कोई सम्बन्ध नहीं था। पीएम मोदी ने हमास द्वारा इजराइल पर आतंकी हमले के समय जो पहला ट्वीट किया उसी से समूचे हिंदू समाज में अलग संदेश जा चुका था। विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने इसका राजनीतिक जवाब देने की नियत से ताबड़तोड़ सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाकर फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया, जिसमें हमास के हमले की कहीं कोई आलोचना नहीं थी। मुस्लिम वोटों को साधने की कांग्रेस की इन कोशिशों का बहुसंख्यक समाज में विपरीत संदेश गया। हैरानी की बात यह थी कि कांग्रेस के अंदरूनी झगड़ों को सुलझाने के लिए सीडब्ल्यूसी की बैठक महीनो नहीं होती। लेकिन विदेश नीति से जुड़े फिलिस्तीन के मुद्दे पर ताबड़तोड़ प्रस्ताव पारित किया गया। विदेश नीति से जुड़े मामले में कांग्रेस सोच समझकर प्रतिक्रिया दे सकती थी। चौथा, मुद्दा खुद राहुल गांधी हैं। ज्यादातर लोगों में यह धारणा है कि 'भारत जोड़ो यात्रा' के रूप में राहुल ने जो कुछ कमाया था, उसका काफी कुछ उन्होंने अपनी दो प्रायोजित विदेश यात्राओं में गंवा दिया।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

यागचूडामण्युपनिषद् (भाग-8)

गतांक से आगे...

रज का संयोग सूर्य में और शुक्ल (शुक्र) का संयोग चन्द्र में जिस प्रकार होता है, उस विषय को और दोनों के एकाकार होने को जानने वाला साधक योगवेत्ता कहा जाता है।

जिस साधना के द्वारा नाड़ी समूह का शोधन किया जाता है तथा सूर्य-चन्द्र को चलाया जाता है एवं रस का शोषण किया जाता है उसे महामुद्रा कहते हैं।

बायें पैर से योनि स्थान पर दबाव डालते हुए, ठोढ़ी को छाती से लगाये और दायाँ पैर सीधा फैलाकर दोनों हाथों से पैर की अंगुलियों सहित पैर पकड़कर दोनों कुक्षियों अर्थात् पेट में पूरा श्वास भरकर धीरे-धीरे बाहर निकाले। यह महामुद्रा की क्रिया समस्त प्रकार की व्याधियों को नष्ट करती है। अभ्यास क्रम में सर्वप्रथम बायीं नासिका चन्द्र अंश से श्वास खींचकर रेचन करते हुए अभ्यास करे, फिर दायीं नासिका सूर्यअंश से श्वास खींचकर रेचन का अभ्यास करना चाहिए। जब दोनों स्वर (चन्द्र-सूर्य) समान हो जाएँ, तब अभ्यास बन्द करना चाहिए। इस महामुद्रा के करने से पथ्य-अपथ्य अथवा सभी तरह का नीरस भोजन सरस हो जाता है। भोजन अधिक कर लेने पर तथा विष भी खा लेने पर वह अमृत के समान पच जाता है। इस महामुद्रा के अभ्यास करने वाले साधक को इसके प्रभाव से क्षय कुष्ठ, गुदावर्त (भगन्दर), गुल्म (तिल्ली बढ़ना), अजीर्ण आदि एवं भविष्य में होने वाले सभी रोगों से छुटकारा मिल जाता है। यह महामुद्रा साधकों को महासिद्धि देने वाली है, इसको हर किसी को (अनधिकारी को) नहीं बताना चाहिए, प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए।

एकान्त स्थान में पद्मासन लगाकर कमर से सिर तक शरीर को सीधा करके नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि को जमाकर अव्यय प्रणव (?) का जप करना चाहिए

(क्रमशः)

अन्तर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस

ललित गर्ग

अन्तर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस प्रतिवर्ष 9 दिसम्बर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर 2003 को संयुक्त राष्ट्र ने एक भ्रष्टाचार-निरोधी समझौता पारित किया था और तभी से यह दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में एक समृद्ध, मूल्याधारित समाज को बनाए रखने के लिए भ्रष्टाचार को खत्म करना इस दिन का मुख्य उद्देश्य है। इस दिन सम्मेलन, भाषण, रैलियां, प्रदर्शनियां, नाटक आदि कई गतिविधियां संयुक्त राष्ट्र और संबंधित सदस्य राज्यों के द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ने की भावना के साथ आयोजित की जाती हैं।

तेजी से पांव पसार रहा भ्रष्टाचार किसी एक समाज, प्रांत या देश की समस्या नहीं है। इसने हर व्यक्ति एवं

व्यवस्था को दूषित किया है, इसे रोकने के लिये प्रतीक्षा नहीं प्रक्रिया आवश्यक है। सत्ता एवं स्वार्थ ने भ्रष्टाचारमुक्ति को पूर्णता देने में नैतिक कायरता दिखाई है। इसकी वजह से लोगों में विश्वास इस कदर उठ गया कि चौराहे पर खड़े आदमी को सही रास्ता दिखाने वाला भी झूठा-सा, भ्रष्ट एवं अनैतिक लगता है। आंखें उस चेहरे पर सच्चाई की साक्षी ढूंढ़ती हैं। भ्रष्टाचार एक गंभीर अपराध है जो सभी समाजों में नैतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास को कमजोर करता है। आज के समय में भ्रष्टाचार से कोई देश, क्षेत्र या समुदाय बचा नहीं है। यह दुनिया के सभी हिस्सों में फैल गया है चाहे वो राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक हो और साथ ही लोकतांत्रिक संस्थानों को भी कमजोर करता है, सरकारी अस्थिरता में योगदान देता है और आर्थिक विकास को भी धीमा करता है, तभी इस विकराल होती समस्या पर नियंत्रण पाने के लिये संयुक्त राष्ट्र ने भ्रष्टाचार निरोध दिवस को आयोजित करने का निश्चय किया।

आसान शब्दों में कहें तो भ्रष्टाचार उन लोगों के द्वारा जिनमें पॉवर होती है एक प्रकार का बेईमान या धोखेबाज आचरण को दर्शाता है। यह समाज की बनावट को भी खराब करता है। यह लोगों से उनकी आजादी, स्वास्थ्य, धन और कभी-कभी उनके जीवन को ही खत्म कर देता है। किसी ने सही कहा है कि भ्रष्टाचार एक मीठा जहर है। विश्व भर में हर साल खरबों डॉलर की रकम या तो रिश्वतखोरी या फिर भ्रष्ट तरीकों की भेंट चढ़ जाती है जिससे कानून के शासन की अहमियत तो कम होती ही है, साथ ही मादक पदार्थों, हथियारों और लोगों की अवैध तस्करी, हिंसा एवं आतंकवाद को भी बढ़ावा मिलता है। हर साल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने वाली खरबों डॉलर की ये रकम वैश्विक घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग 5 फीसदी के बराबर है। इसके कारण राष्ट्रों की समृद्धि से ज्यादा साख खतरे में पड़ी है। आज हमारे कंधे भी इसीलिये झुक गये कि भ्रष्टाचार का बोझ सहना हमारी आदत हो गयी है। भ्रष्टाचार के नशीले अहसास में रास्ते गलत पकड़ लिये और इसीलिये भ्रष्टाचार की भीड़ में हमारे साथ गलत साथी, संस्कार, सलाह, सहयोग जुड़ते गये।

कांग्रेस की तंगदिली के चलते बिखरने लगा है विपक्षी गठबंधन

डॉ. आशीष वशिष्ठ

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। देशभर फिलवक्त चर्चा हिंदी पट्टी के तीन राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत की है। बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बचाने में सफल रही और पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हराकर बीजेपी सत्ता में लौट आई है। वहीं राजस्थान में हर चुनाव में सरकार बदलने का रिवाज बदलना चाह रही कांग्रेस नाकामी हाथ लगी है। उसे सिर्फ दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में ही सफलता मिली है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रचंड जीत ने चुनावी पंडितों को हैरान कर दिया है, वहीं तेलंगाना और मिजरोम में बीजेपी के बढ़ते जनाधार ने इंडी गठबंधन में खलबली मचा दी है। कांग्रेस के लचर और निराशाजनक प्रदर्शन का असर इंडी गठबंधन की एकजुटता पर भी दिखाई देने लगा है। सवाल उठ रहे हैं कि इन नतीजों का इस गठबंधन और इसके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए भी, क्योंकि नतीजों के बाद इंडिया के घटक दलों ने कांग्रेस के रवैए पर सवाल उठाए हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को इंडी गठबंधन की बैठक बुलाई थी। लेकिन बैठक से ठीक एक दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बैठक में शामिल होने से इंकार कर दिया। कांग्रेस की तरफ से सफाई दी गई है कि बारिश की वजह से चेन्नई एयरपोर्ट बंद है, ऐसे में स्टालिन भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं हैं, जबकि ममता बनर्जी कार्यक्रम में व्यस्त है। गठबंधन के कई सहयोगियों के इनकार के बाद इंडी गठबंधन की बैठक को

टालना पड़ गया है। अब कांग्रेस के सामने अपने कुनबे को बचाये रखने की चुनौती है।

कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन से इंडी गठबंधन के घटक दलों को प्रेशर पॉलिटिक्स करने का मौका मिल गया। इंडी गठबंधन में शामिल दल अब कांग्रेस को गठबंधन धर्म पालन नहीं करने की याद दिला रहे हैं। साथ ही बता रहे हैं कि गठबंधन न करने का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। ऐसे में घटक दल कांग्रेस की आपदा में अपना अवसर तलाश रहे हैं। अपनी शर्तों पर कांग्रेस से समझौता करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने बैठक से दूरी बनाकर कांग्रेस को स्पष्ट संदेश दे दिया है। इंडी गठबंधन की दूसरी बैठक के बाद ही ममता बनर्जी ने जो तेवर दिखाया था, उससे पता चल गया था कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसके बाद बैठक में शामिल होने से इंकार कर ममता बनर्जी ने अपनी नाराजगी प्रकट कर दी है। हालांकि उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि बैठक कब और कहां हो रही है इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। किसी ने मुझे बैठक के बारे में नहीं बताया था और ना ही कोई फोन आया था। अगर उन्हें पता होता तो बैठक में चली जाती है। इसके विपरीत कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सभी नेताओं को बैठक की सूचना दे दी गई थी। ममता बनर्जी की सफाई और कांग्रेस के बचाव ने गठबंधन की पोल खोलकर रख दी है। इससे पहले कांग्रेस की हार पर ममता बनर्जी से सवाल किया गया तो उन्होंने दो टूक कहा कि ये जनता की नहीं कांग्रेस की हार है। कांग्रेस की हार 'ज़मींदारी एटीट्यूड' की वजह से हुई है। वहीं जनता दल यूनाइटेड का कहना है कि कांग्रेस के 'घमंड' की वजह से हार मिली है।

वास्तव में पांच राज्यों में चुनाव से पहले कांग्रेस हसीन सपने देख रही थी। उसे चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। इसके माध्यम से वो अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने और इंडी गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर मजबूती के साथ बैठकर मनमाना फैसले लेने की सोच रही थी। लेकिन खराब प्रदर्शन ने उसके उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब बाजी पूरी तरह पलट गई है। अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और उसे इंडी गठबंधन के घटक दलों की नसीहत, शर्तों और बार्गेनिंग से जूझना पड़ रहा है। आने वाले समय में घटक दलों के दबाव और हमलों और बढ़ेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने इन चुनावों में एक मौक़ा गंवाया है। इन चुनावों में विपक्षी दलों को साथ लेने और एक राजनीतिक बदलाव की पहल कांग्रेस कर सकती थी, जिससे इंडिया गंठबंधन की भावना को मज़बूती मिलती। छोटी पार्टियों को अपने साथ लेने से कांग्रेस को जो फ़ायदा मिल सकता था, उसमें उसने चूक की है। गठबंधन बनने से जो राजनीतिक शक्ल बदलती है, वह विधानसभा चुनाव में नहीं बदली। जैसे तेलंगाना में कांग्रेस ने सीपीआई के साथ गठबंधन किया था, लेकिन सीपीएम के साथ नहीं किया था। तो इस तरह से बाक़ी जगह भी छोटे दलों को साथ लाने का फ़ायदा वे नहीं ले पाए। छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का वोट बीजेपी को ट्रांसफ़र हो गया। इसी तरह कांग्रेस राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के साथ गठबंधन कर सकती थी। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहती थी तो एक-दो सीटें उन्हें दी जा सकती थीं। कुछ सीटें वामदलों को कांग्रेस दे देती तो नई राजनीति ला सकते थे। लेकिन कांग्रेस भी साफ्ट-हिंदुत्व के फेर में पड़ गई। लेकिन कांग्रेस ने न हिंदुत्व को चुनौती दी, न ही उस पर खेल पाई। और कांग्रेस की इन तमाम चूकों का नतीजा अब सबके सामने है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगर छोटे दलों को साथ लिया जाता तो फ़ायदा होता। जैसे समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में मौक़ा दिया जाता, तो बिहार और यूपी के स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने और स्वीकार्यता बनाने का अवसर मिलता। लेकिन अभी इसके लिए लंबी लड़ाई की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पर ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा ही नहीं था। वास्तव में, इंडिया गठबंधन पहले ही दिन से कई चुनौतियों से जूझ रहा है। जैसे इसके घटक दल कई राज्यों में एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी हैं और वे एक-दूसरे के विरुद्ध चुनाव भी लड़ते रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न मुद्दों और विषयों पर उनकी राय और स्टैंड भी अलग है। मध्य प्रदेश चुनाव में गठबंधन नहीं होने से अखिलेश यादव पहले ही मोर्चा खोल चुके हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पहले ही कांग्रेस और लेफ्ट से सीट शेयरिंग को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। नीतीश कुमार भी समय-समय पर आंखें दिखाते रहते हैं। ऐसे में कांग्रेस अब घटक दलों के सामने पूरी तरह बेबस और लाचार हो चुकी है। वहीं यह भी ज़रूरी नहीं कि जो विधानसभा चुनाव में हुआ, वैसा ही लोकसभा में होगा। लेकिन जो चाहते हैं कि सत्ता में बदलाव हो, उनका काम मुश्किल जरूर हो गया है। केंद्र से बीजेपी को हटाना है तो उसे गुजरात से लेकर बिहार तक हराना ज़रूरी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस के पास ले-देकर अभी तीन से चार ही लोकसभा सीटें हैं।

आज का इतिहास

1917 प्रथम विश्व युद्ध-हुसैन अल-हुसैनी, तुर्क मेयर ऑफ जेरूसलम ने शहर को अंग्रेजों के हवाले कर दिया।

1931 कॉन्स्टिट्यूड कॉर्टेस द्वारा स्पैनिश संविधान की स्वीकृति ने दूसरे स्पैनिशरिपोलिस की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया।

1938 इस्तवान शिशकी हंगरी के विदेश मंत्री बने।

1940 द्वितीय विश्व युद्ध-ब्रिटिश और राष्ट्रमंडल बलों ने ओपनऑपरेशन कम्पास खोला, जो वेस्टवर्न डेजर्ट अभियान का पहला प्रमुख सहयोगी सैन्य अभियान था।

1941 चीन ने जापान,जर्मनी और इटली के खिलाफ युद्ध की घोषणा की।

1958 जॉन बिर्च सोसाइटी, जिसका नाम जॉन बिर्च है, एक अमेरिकी प्रवेशकर्ता जो कम्युनिस्टों द्वारा चीन में मारा गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में साम्यवाद के कथित खतरे से लड़ने के लिए स्थापित किया गया था।

1965 चार्ल्स शुलज की कॉमिक स्ट्रिप मूंगफली का पहला टेलीविजन रूपांतरण चार्ली ब्राउन क्रिसमस पहली बार प्रसारित किया गया था।

1968 डगलस एंगेलबार्ट ने ओएन-लाइन सिस्टम (एनएलएस) का उपयोग करके कंप्यूटर माउस (चित्र), हाइपरटेक्स्ट, और बिट मैप्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सार्वजनिक रूप से चर्चित करते हुए %द मदर ऑफ ऑलडेमोस% के रूप में जाना।

1974 पेरिस के शिखर सम्मेलन में यूरोपीय समुदाय के राज्यों और सरकार के प्रमुखों के पुनर्मिलन शुरू हुए।

1979 वैज्ञानिकों के एक विश्व स्वास्थ्य संगठन आयोग ने चेचक के वैश्विक उन्मूलन को प्रमाणित किया, जिससे यह अब तक का एकमात्र मानव संक्रामक रोग है जो प्रकृति से पूरी तरह से समाप्त हो गया है।

1992 ब्रिटेन के शाही जोड़े प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेज डायना के अलग होने की आधिकारिक घोषणा हुई थी।

2001 यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।

2003 मास्को के केंद्र में एक विस्फोट से छह लोगों को मौत हुई और भी कई घायल हुए।

2007 रॉबर्ट पिकटन को वैंकूवर के डाउनटाउन ईस्टसाइड की छह महिलाओं की दूसरी डिग्री की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।

नये कल्याणकारी राज्य का आरंभ

डॉ अश्विनी महाजन

राजनीतिक विश्लेषक राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत के कारणों का विश्लेषण कर रहे हैं। भाजपा चुनाव में अक्सर कांग्रेस की सांप्रदायिक वोट बैंक, भ्रष्टाचार, वंशवाद आदि की राजनीति के मुद्दे उठाती रही है। राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 को समाप्ति, सांप्रदायिक हिंसा जैसे मुद्दे काफी चर्चा में रहे। लेकिन इतिहास गवाह है कि चाहे ये मुद्दे महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन यदि कोई पार्टी या सरकार लोगों की भलाई के लिए काम नहीं करती, तो जनता उसे स्वीकार नहीं करती। भाजपा को मध्य प्रदेश में 48.81 प्रतिशत, राजस्थान में 41.85 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 46.35 प्रतिशत वोट मिलना यह दर्शाता है कि पार्टी की केंद्र सरकार की योजनाओं और उनकी उपलब्धियों से जनता संतुष्ट है और इसलिए उसकी सरकार चाहती है।

वंशवाद, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक हिंसा के बारे में भी जनता संवेदनशील है और देश में स्वस्थ एवं विकासवादी राजनीति की स्थापना चाहती है। वह वोट बैंक की राजनीति के चलते आर्थिक एवं सामाजिक वातावरण को दूषित भी नहीं होने देना चाहती। आम जन इस दंश के साथ जी रहा था कि भारत एक गरीब देश है, जो अमीर देशों की अकूत संपत्ति, विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर, उच्च आमदनी और जीवन स्तर का मुकाबला कर ही नहीं सकता। उनके बराबर पहुंचने में हमें कई सदियां भी लग सकती हैं।

साल 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे जर्जर पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल थी। लेकिन 10 वर्षों से भी कम समय में भारत विश्व की दसवीं अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ता हुआ पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था तक पहुंच गया है और अगले तीन सालों से भी कम समय में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज भारत विश्व की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भी बन चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने से पहले एक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प देकर आम जन की आकांक्षाओं को नये पंख देने का काम किया है। स्वाभाविक है कि जनता ने भाजपा पर अपना भरोसा जताया है। पिछले कुछ समय से कुछ राज्यों में सरकारों और दलों द्वारा बड़ी मात्रा में मुफ्त की योजनाओं के दम पर सत्ता पर काबिज होने का प्रयास शुरू हुआ है। उन्हें कुछ हद तक सफलता भी मिलती हुई दिख रही है।

दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकारों द्वारा मुफ्त की योजनाओं की झड़ी लगी हुई है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी ऐसी कई योजनाएं चल रही हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन योजनाओं को चलाने हेतु इन सरकारों के पास पर्याप्त धन की भारी कमी है। इस कारण वे एक ओर तो भारी कर्ज में डूबते जा रहे हैं, तो दूसरी ओर इन योजनाओं के कारण वे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आम जन को सशक्त बनाने वाली अन्य योजनाओं पर खर्च नहीं कर पा रहे हैं। हालिया चुनावों में भी दलों ने मुफ्त योजनाओं की कई घोषणाएं कीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में किसानों के कर्ज माफ करने के अलावा, मुफ्त बिजली, गैस सिलेंडर की सब्सिडी, महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह, युवाओं को 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ते के अलावा आदि स्कीमों की घोषणा की। राजस्थान में पहले से ही कांग्रेस सरकार महिलाओं को स्मार्टफोन, सस्ता सिलेंडर, 25 लाख रुपये तक के इलाज के लिए फ्री मेडिकल बीमा, एक करोड़ परिवारों को फ्री फूड पैकेट आदि की योजनाएं तो चला ही रही थी, इस चुनाव में उसने फ्री लैपटॉप, फ्री बिजली आदि की भी घोषणा की थी।

हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ऐसी मुफ्त की योजनाओं को गलत मानते हैं और इसे रेवड़ी बांटने की संज्ञा देते हैं, इसके बावजूद भाजपा और उसकी सरकारों ने बड़ी मात्रा में कई ऐसी योजनाओं को चलाया है, जिसमें उज्जवला लाभार्थियों और आम जन को सस्ता सिलेंडर देना, राजस्थान में 12वीं कक्षा पास करने के बाद लड़कियों को फ्री स्कूटी देना आदि की घोषणा भी शामिल है। लेकिन यह भी सच है कि मुफ्त बिजली, पानी और यात्रा आदि योजनाओं से भाजपा ने हमेशा परहेज रखा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रेवड़ियां बांटने और नयी रेवड़ियों की घोषणा के बावजूद तीन राज्यों में कांग्रेस जीत नहीं पायी।

अभी तक रोजगार योजनाओं के माध्यम से पैसे बांटने, मुफ्त या सस्ती बिजली-पानी, पेट्रोल, डीजल और गैस पर सब्सिडी, सस्ता राशन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च आदि तक सीमित रहना ही कल्याणकारी राज्य मान लिया जाता था। लेकिन पिछले नौ सालों में कल्याणकारी राज्य की परिभाषा बदली है और उसमें सुधार दिख रहा है, जिसे जनता का समर्थन भी प्राप्त हुआ है। सबसे पहले आवास योजना में आमूल चूल परिवर्तन के माध्यम से प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए खर्च की वास्तविकता को सुनिश्चित करने का प्रयास हुआ है। कुछ ही सालों में लगभग तीन करोड़ घरों का निर्माण हुआ, जिसमें पांच लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिये गये और 15 लाख करोड़ रुपये स्वयं लाभार्थियों ने खर्च कर अपने लिए बेहतर घरों का निर्माण किया। एक करोड़ अतिरिक्त घरों का निर्माण भी विभिन्न चरणों में है।

उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया गया। लगभग सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने से जीवन स्तर में सुधार तो हुआ ही है, संचार और इंटरनेट क्रांति को देशभर में ले जाने में भी सफलता मिल रही है। सभी घरों में नल से जल का लक्ष्य भी पूर्ण होने के कगार पर है। हर घर में शौचालय बनने से खुले में शौच जैसे अभिशाप से मुक्ति हुई है, जिसके चित्र दिखाकर भारत को पिछड़ा दिखाने का प्रयास विदेशी अक्सर किया करते थे।

प्राथमिक चिकित्सा में सुधार और सबसे महत्वपूर्ण आयुष्मान योजना के तहत पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज, कम साधन संपन्न लोगों के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। ये सभी योजनाएं लक्षित लाभार्थियों के लिए हैं। पूर्व में राजनीतिक दल उनकी गरीबी, अभाव और बेरोजगारी को दूर करने के छलावों से उनके वोट बटोर लिया करते थे। अब इन लाभार्थियों ने पिछले 9-10 सालों में सरकार की मदद और स्वयं के प्रयासों से इन अभावों से कुछ हद तक मुक्ति पायी है। शायद राजनीतिक दलों की मुफ्त की रेवड़ी योजना से ज्यादा वोटरों को नया कल्याणकारी राज्य का अवतार भा रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के अनुसार, 2015-16 से 2019-21 के मात्र पांच सालों में बहुआयामी गरीबी का सूचकांक 0।122 से घटकर 0।69 तक पहुंच चुका है। इस अवधि में लगभग 14 करोड़ अतिरिक्त लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। आज बदलती हुई परिस्थितियां देश में नयी राजनीति को जन्म दे रही हैं और देश विकसित देश बनने की ओर अग्रसर हो रहा है।

राजस्थान में कांग्रेस को आपसी कलह विधानसभा चुनाव में ले डूबी

रमेश सर्राफ धमोरा

राजस्थान विधानसभा चुनाव में लोगों को जैसी अपेक्षा थी उसी के अनुरूप चुनाव परिणाम देखने को मिले हैं। पिछले पांच विधानसभा चुनाव से प्रदेश में हर बार राज बदलने की परंपरा छठी बार भी कायम रही है। अशोक गहलोत के लाख प्रयासों के उपरांत भी कांग्रेस पार्टी प्रदेश में हर बार सत्ता बदलने का रिवाज नहीं बदल पाई और सत्ता गंवा दी। राजस्थान के मतदाताओं ने भाजपा की भारी बहुमत से ताजपोशी की है ताकि अगले पांच साल तक वह बिना किसी बाधा के राज कर सके। प्रदेश में भाजपा 115 सीटों के पर्याप्त बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। वहीं कांग्रेस का आंकड़ा 108 से घटकर 69 सीटों पर ही सिमट गया है। प्रदेश के मतदाताओं ने तीसरे मोर्चे के नाम पर नेतागिरी कर रहे बड़बोले नेताओं को भी चुनाव में उनकी जगह दिखा दी है। बहुजन समाज पार्टी मात्र दो सीटों पर सिमट गई। वहीं सत्ता की चाबी अपने हाथ में होने का दावा करने वाले नागौर के सांसद व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल अपनी खुद की खींवसर विधानसभा सीट पर मात्र 2059 मतों के अंतर से जीत सके हैं। उनकी पार्टी के सभी प्रत्याशी पराजित हो गए। चुनाव से कुछ महीना पहले ही बांगड़ के आदिवासी क्षेत्र में बनाई गई भारतीय आदिवासी पार्टी के तीन विधायक जीतने में सफल रहे हैं। हालांकि भारतीय आदिवासी पार्टी आदिवासी क्षेत्र में पहले भारतीय ट्राईबल पार्टी के नाम से पिछले विधानसभा चुनाव में उतरी थी और उसके दो विधायक जीते थे। उन्हीं दोनों विधायकों ने भारतीय आदिवासी पार्टी के नाम से नई पार्टी का गठन किया था। आठ निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। जिनमें से एक कांग्रेस का व सात भाजपा के बागी थे। विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत ने चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। मगर कांग्रेस में चल रही आपसी गुटबाजी के चलते मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी को सिरे से ठुकरा दिया। विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही पार्टी के मुख्य चेहरे बने हुए थे। उन्हीं के चेहरे पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। पार्टी की सभी प्रचार सामग्री पोस्टर, बैनर और होर्डिंगों में अशोक गहलोत ही छाए हुए थे। अशोक गहलोत द्वारा हायर की गई प्रचार कंपनी डिजाईन बाक्स व उसके बड़बोले निदेशक नरेश अरोड़ा भी चुनाव जितवाने में नाकाम रहे। सचिन पायलट पूरे चुनाव में ही साइड लाइन रहे। टिकट वितरण के दौरान सचिन पायलट ने जिस तरह से गहलोत के सामने हथियार डाले दिये थे। उस पर बड़े-बड़े राजनीतिक विश्लेषकों को भी आश्चर्य हुआ था। चुनाव से पहले शुचिता की बड़ी-बड़ी बातें करने वाले पायलट ने जिस तरह से गहलोत समर्थक शांति धारीवाल और प्रमोद जैन भाया जैसे विवादित लोगों को टिकट देने पर अपनी सहमति जताई उससे सभी अचंभित रह गए। लोगों का कहना था कि पायलट ने अपने समर्थक कुछ लोगों के टिकट क्लीयर करवाने के चक्कर में गहलोत से अंदर खाने अघोषित समझौता कर लिया था। चुनाव में पायलट के कहने पर करीबन 40 लोगों को टिकट मिली जबकि गहलोत समर्थकों की संख्या 150 से भी ऊपर थी। चुनाव से पहले गहलोत बार-बार कहते थे कि प्रदेश की जनता में सरकार के खिलाफ नकारात्मक माहौल नहीं है। जनता प्रदेश सरकार के कामों से खुश है। विधायकों को लेकर जनता में नाराजगी है। इसलिए हम बड़ी संख्या में नए लोगों को मैदान में उतरेंगे। मगर चुनाव आते-आते सारी बातें कागजों में ही रह गई और धड़ाधड़ बूढ़े व मौजूदा विधायकों को मैदान में उतार दिया गया। जिसका नतीजा कांग्रेस को करारी हार के रूप में देखना पड़ा। अशोक गहलोत ने सबसे बड़ी गलती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सामने खुद को चेहरा बना कर कर दी। राजस्थान में भाजपा ने किसी को भी चेहरा बनाकर चुनाव नहीं लड़ा था। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे व कमल के फूल के निशान पर चुनाव लड़ा था। वहीं अशोक गहलोत ने सामूहिक नेतृत्व के स्थान पर खुद को ही आगे कर पूरी चुनावी व्यूह रचना की थी जिसमें वह नाकाम रहे। कई विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को अपने बागी प्रत्याशियों की नाराजगी के चलते भी हार का सामना करना पड़ा है। समय रहते कांग्रेस पार्टी आंतरिक बगावत पर नियंत्रण नहीं कर पाई। पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा व तीनों सह प्रभारी का तो चुनाव के दौरान पता ही नहीं चला कि वो कहां रहे।

2023 के नतीजों ने भाजपा के लिए आसान की 2024 की राह

नीरजा चौधरी

रविवार को चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो परिणाम घोषित हुए हैं, वे भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साहजनक हैं। भाजपा ने न केवल मध्य प्रदेश में चार कार्यकाल की सत्ता विरोधी रुझानों के बावजूद बिना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए शानदार ढंग से सत्ता में वापसी की है, बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से सत्ता छीन ली है। कह सकते हैं कि राजस्थान में पांच वर्ष पर सत्ता बदलने का पुराना रिवाज है, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल द्वारा चलाई गई तमाम कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद भाजपा ने सत्ता हासिल की है। दक्षिण भारतीय राज्यों में भाजपा की कोई खास पैठ नहीं है, इसलिए तेलंगाना में मुख्य लड़ाई के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस (पहले टीआरएस) और कांग्रेस के बीच थी। चूंकि वहां केसीआर के रवैये और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण बीआरएस के खिलाफ जबर्दस्त सत्ता विरोधी रुझान था, इसलिए वहां सत्ता हासिल करना कांग्रेस के लिए आसान हो गया। इसके अलावा, रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में वहां पार्टी का संगठन भी अपेक्षाकृत मजबूत है। इन चारों राज्यों के जनादेश का अगर विश्लेषण करें, तो एक बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि हिंदी भाषी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ बहुत मजबूत है। यह इससे भी स्पष्ट है कि वर्ष 2018 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत के तुरंत बाद 2019 में हुए चुनावों में इन राज्यों में भाजपा ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। इस बार तो इन राज्यों में भाजपा ने जीत दर्ज की है, इसलिए 2024 में उसके लिए जीतना और आसान होगा। इसका एक मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि जहां-जहां कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर होती है, संगठन और चुनावी मशीनरी के मामले में काफी कमजोर होने के कारण कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ जाती है और जहां कांग्रेस का मुकाबला क्षेत्रीय पार्टियों से होता है, वहां उसे सफलता मिलती है। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आज भी बरकरार है। इन सभी राज्यों में भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था और मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था। बेशक इन चुनावों में भाजपा की जीत के पीछे और भी कई मुद्दे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी का चेहरा एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। जाहिर है, मतदाता उन पर भरोसा करते हैं। बूथ स्तर तक भाजपा का संगठन मजबूत है और पार्टी की चुनावी मशीनरी हमेशा सक्रिय रहती है। लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी और भी मजबूती के साथ पार्टी का चेहरा बनकर उभरेंगे।

राजस्थान में जनता ने कांग्रेस को सबक भी सिखाया

निरंजन परिहार

राजस्थान में कांग्रेस की हार के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है और राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनको अगली सरकार बनने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कह दिया है। गहलोत के इस्तीफे का कारण यही है कि राजस्थान में राज बदल गया मगर रिवाज नहीं बदला। राज बदलते ही मुख्यमंत्री का इस्तीफा वाजिब था। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे थे कि न तो राजस्थान में राज बदलेगा और रिवाज भी नहीं बदलेगा। उनका मतलब था कि कांग्रेस की सरकार फिर आएगी और हर पांच साल में सत्ता परिवर्तन का जो रिवाज है वह इस बार बदल जाएगा। मगर, ऐसा नहीं हो सका। राजनीति में वैसे भी नेता के मन का होता कहां है, होता तो आखिर वही है जो जनता चाहती है। जनता ने चाहा और राज बदल गया। कांग्रेस चली गई, और गहलोत भी जा रहे हैं। नई सरकार के शपथ लेते ही वे भी भूतपूर्व हो जाएंगे।

राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य को सही मायने में देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के नतीजों में कुछ भी नया नहीं है। तीन दशक से राजस्थान में हर पांच साल में सरकार को घर बिठाने की परंपरा रही है। एक बार कांग्रेस तो दूसरी बार बीजेपी। बारी-बारी से दोनों पार्टियों को लोग सरकार में लाते रहे हैं। हालांकि, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल में गहलोत ने समाज के हर वर्ग के लिए सरकार के खजाने खोल कर कुछ अलग तरह की जादूगरी दिखाने के सारे प्रयास किए, लेकिन उनके मंत्रियों व विधायकों के भ्रष्टाचार के कारण उनका जादू हर स्तर पर लगातार फेल होता ही नजर आया। हालांकि, गहलोत हर संभव कोशिश करते रहे। सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देकर एक बड़े वर्ग को साधने के लिए सरकार के दांव को परफेक्ट समझना कहीं न कहीं बड़ी गलती रही, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों ने ही उनको वोट नहीं दिया। फिर महिला सशक्तिकरण के नाम पर

योजनाओं और धन लक्ष्मी जैसी योजनाओं का भी असर ग्राउंड स्तर पर ज्यादा लाभकारी साबित नहीं हो सका, क्योंकि सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने वाले कार्यकर्ता कांग्रेस के पास नहीं थे। सही मायने में देखें, तो जनता को जो सबसे बड़ा लाभार्थी तबका, जिसको लेकर कांग्रेस आश्वस्त थी कि वह उसी को वोट देगा, वही साथ छोड़कर बीजेपी के साथ खड़ा हो गया और कांग्रेस उसे समझ भी नहीं सकी।

राजस्थान में कांग्रेस के 30 विधायक कम पड़ गए हैं। पिछली विधानसभा में 99 थे मगर अब 69 ही जीते हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस सरकार के 17 मंत्रियों सहित मुख्यमंत्री के 5 सलाहकार भी चुनाव हार गए हैं। ये सभी 17 मंत्री, गोविन्द राम मेघवाल, भंवर सिंह भाटी, रमेश मीणा, परसादी लाल मीणा, विश्वेन्द्र सिंह, प्रताप सिंह खाचरियावास, ममता भूपेश, शकुंतला रावत, राजेंद्र यादव, बीडी कल्ला, सालेह मोहम्मद, राम लाल जाट, सुखराम विश्नोई, उदयलाल आंजना, जाहिदा खान, प्रमोद जैन भाया और भजन लाल जाटव राजस्थान सरकार में काफी महत्वपूर्ण विभाग के मुखिया थे तथा गहलोत सरकार के ताकतवर नेता थे। मगर प्रदेश की जनता ने उन्हें हरा दिया।

इनके अलावा विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और पूर्व मंत्री रघु शर्मा भी चुनाव हार गए। यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो सरकार अपने विकास व जनसेवा के कार्यों को जबरदस्त अभियान के तहत जनता तक ले गई, उसी सरकार के 17 मंत्री, 5 सलाहकार व दस बड़े नेता चुनाव हार गए।

देखा जाए, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने इस बार के 5 साल के कार्यकाल में सबसे पहले तो अपने साथी सचिन पायलट से जूझते रहे, फिर लगभग डेढ़ साल तक कोरोना से जूझे, एक के बाद एक घोषणाओं और योजनाओं के दौर चले। जमता को अपनी योजनाओं से लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हुए वे अपनी सरकार बचाने के भी हर कोशिश करते रहे। इसे इन शब्दों में भी कहा जा सकता है कि गहलोत ने एक तरह से अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, जिसके लिए उन्होंने सरकारी खजाने के खाली होने की भी परवाह नहीं की। खासकर एक के बाद एक योजनाओं के जरिए महिला सशक्तिकरण और पिछड़े इलाकों के विकास के लिए जमीनी स्तर पर काम भी बहुत बड़े पैमाने पर किया गया। मगर कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उससे चूक कहां हो गई, जो राजस्थान की जनता उसके बजाय बीजेपी को बहुमत देकर उसके साथ खडी हो गई।

राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता से खदेड़ने के कारण तलाशे जा रहे हैं। क्या कांग्रेस की अंदरूनी कलह पार्टी के लिए बुरी हार का कारण बनी, या पार्टी का लचर संगठन हारने के लिए जिम्मेदार रहा, या फिर राज्य की जनता को नए नेतृत्व की चाह थी। क्या बाबा बालकनाथ के नाम पर यूपी की तरह राजस्थान में भी योगी फैक्टर चला या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का अटूट विश्वास था और या फिर वसुंधरा राजे पर एक बार फिर लोगों ने विश्वास जताया। कांग्रेस समझ ही नहीं पा रही है कि उसको सत्ता से बेदखल क्यों होना पड़ा। इन सारे ही सवालों में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों इतना सब करने के बाद भी कांग्रेस की हालत इतनी खराब हुई। दरअसल कांग्रेस की अंतर्कलह से प्रदेश की जनता खुद ही परेशानी में थी।

मध्य प्रदेश की बंपर जीत का गणित

सिद्धार्थ शंकर गौतम

मध्य प्रदेश में भाजपा की एकतरफा प्रचंड जीत का कई प्रकार से परीक्षण हो रहा है। लेकिन यहां भाजपा की उस रणनीति पर विचार करने की जरूरत है जो उसने स्थानीय स्तर पर पार्टी प्रबंधन और चुनाव प्रचार के लिए अपनाई। इसके लिए भाजपा ने जहां एक ओर प्रदेश स्तर पर तैयारी की वहीं संभागवार जीत की रणनीति भी बनायी।

मध्य भारत संभाग बीते एक दशक से भाजपा का मजबूत गढ़ बनकर उभरा है। मध्य प्रदेश के आठ जिलों भोपाल, सीहोर, विदिशा, नर्मदापुरम, रायसेन, राजगढ़, हरदा और बैतूल की 36 विधानसभा सीटों में से 31 पर भाजपा प्रत्याशी की जीत यह इंगित करती है कि यह क्षेत्र अब भगवा रंग से सराबोर हो चुका है। 2018 के मुकाबले कांग्रेस को इस संभाग से 7 सीटों का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी क्षेत्र की बुधनी विधानसभा से चुनाव जीते हैं। विदिशा (5 सीटें), नर्मदापुरम (4 सीटें), राजगढ़ (5 सीटें), सीहोर (4 सीटें) और बैतूल (5 सीटें) विधानसभा में कांग्रेस-मुक्त हो गए हैं।

दिग्विजय सिंह के प्रभाव वाला राजगढ़ जिला पहली बार कांग्रेस को चकित कर गया। मात्र हरदा जिले की दोनों विधानसभाओं हरदा और टिमरनी में कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी हुए हैं किन्तु उनकी जीत का अंतर क्रमश: 870 तथा 950 वोट है। भोपाल जिले की बात की जाए तो 7 विधानसभा सीटों में से 5 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस काबिज हुई है। कांग्रेस के दोनों विधायक मुस्लिम समुदाय से हैं और इनका वर्चस्व यहां लंबे समय से है। भोपाल को लेकर एक दिलचस्प आंकड़ा यह है कि भोपाल लोकसभा सीट पर 1984 में कांग्रेस के केएन प्रधान सांसद बने थे और इसके बाद भोपाल गैस कांड के चलते कभी कांग्रेस इस लोकसभा से जीत नहीं पाई। यह समीकरण कई विधानसभा सीटों पर भी चलता है।

2018 में भाजपा को सर्वाधिक नुकसान जिस ग्वालियर-चंबल संभाग से हुआ था और पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया (तब कांग्रेस में थे) के करिश्मे के चलते 34 में से मात्र 7 सीटों पर ही जीत पाई थी, इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया (अब भाजपा में) और नरेन्द्र सिंह तोमर की जुगलबंदी के चलते 18 सीटों पर विजयी रही है। कांग्रेस को यहां 10 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि ग्वालियर-चंबल संभाग में सिंधिया की छवि के उलट उनके 7 समर्थक %कमल दल% से हार गए जो उनके लिए सदमे जैसा है।

दरअसल, 2018 में सिंधिया के साथ मिलकर जिन 22 विधायकों ने कमलनाथ सरकार गिराई थी, इनमें 19 सिंधिया समर्थक थे। इस बार 19 में से 13 समर्थकों को सिंधिया टिकट दिलाने में कामयाब रहे थे किंतु उनके 6 समर्थक ही जीत हासिल कर सके जबकि सिंधिया ने अपने समर्थकों को जिताने के लिए 70 सभाएं और रोड शो किए थे। ऐसा कहा जा रहा है कि संभाग में %महल विरोध% की राजनीति एक बार फिर सिंधिया की भाजपा में स्वीकार्यता की अग्निपरीक्षा लेगी।

कहते हैं कि मध्य प्रदेश में सत्ता का रास्ता मालवा-निमाड़ से होकर ही गुजरता है। 2018 में संभाग की 66 सीटों में से भाजपा को 29 और कांग्रेस को 34 सीटें मिली थीं। तब मंदसौर में किसान गोलीकांड, वनवासी

वर्ग का भाजपा से मोहभंग और कांग्रेस की एकजुटता ने कमल के निशान को कुंद कर दिया था किंतु इस बार भाजपा को संभाग से 19 सीटों का लाभ हुआ है। भाजपा ने अपनी गलतियों से सीखकर 2020 से ही क्षेत्र में वनवासी समुदाय के हितों का संरक्षण, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की बड़ी आबादी को लाभार्थी बनाना, केंद्र-राज्य की योजनाओं की मानिटरिंग करना प्रारंभ कर दिया था। शहरी क्षेत्र तो पहले से भाजपा के पक्ष में था, इस बार ग्रामीण क्षेत्र में भी कमल खिला है। इंदौर जिले की 9 विधानसभाओं पर भाजपा प्रत्याशियों की जीत हुई है। इसके अलावा इंदौर जिले के 4 नेताओं ने संभाग के अन्य जिले से जीत हासिल कर प्रदेश की राजनीति में इंदौर के दबदबे को साबित किया है। संभाग में भाजपा की प्रचंड जीत के सूत्रधार कैलाश विजयवर्गीय रहे जिन्होंने 10 से अधिक बागियों को भाजपा के पक्ष में काम करने के लिए मनाया और अपने कई समर्थकों के लिए प्रचार करके उन्हें भी जीत दिलाई।

यह भी दिलचस्प तथ्य है कि विजयवर्गीय ने अपने राजनीतिक जीवन में 4 अलग विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा और जहां भी वे लड़े, वे सीटें %भाजपा की अयोध्या% बन गईं। कांग्रेस के पास उन सीटों पर लड़ाने के लिए उम्मीदवारों का टोटा रहता है और रस्म-अदायगी की तर्ज पर वहां प्रत्याशी उतारे जाते हैं। हालांकि रतलाम जिले की सैलाना सीट से %बाप% (भारत आदिवासी पार्टी) उम्मीदवार कमलेश्वर डोडियार की जीत ने भाजपा-कांग्रेस को चौंका दिया है।

बात यदि उत्तर प्रदेश से सटे बुंदेलखंड की करें तो यहां भाजपा को 26 में से 21 सीटें प्राप्त हुई हैं और पार्टी को 2018 के मुकाबले 4 सीटों का लाभ हुआ है। यहां कांग्रेस 2018 के मुकाबले मात्र 2 सीटों के नुकसान में रही है। चूंकि यहां सपा-बसपा का भी प्रभाव रहता है अत: ऐसा माना जा रहा था कि इससे भाजपा को नुकसान होगा किंतु भाजपा ने सपा-बसपा के 1.5 प्रतिशत वोट को ही अपने पाले में कर लिया। हालांकि भाजपा को पृथ्वीपुर और टीकमगढ़ सीट पर हार मिली है जिसका कारण सपा मानी जा रही है। संभाग में पन्ना (3 सीटें) और दमोह (4 सीटें) जिले कांग्रेस मुक्त हो गए हैं जबकि सागर जिले में भाजपा 7-1 और छतरपुर जिले में 5-1 से आगे है।

विंध्य संभाग भी एक दशक से भाजपा का अभेद किला बन चुका है। एक समय प्रदेश का यह पूर्वी इलाका कांग्रेसी दिग्गज %सफेद शेर% स्व. श्रीनिवास तिवारी और स्व. अर्जुन सिंह का गढ़ माना जाता था और प्रदेश में ओबीसी राजनीति की शुरुआत भी यहीं से हुई थी किंतु समय के साथ विंध्य से कांग्रेस साफ होती गई और वर्तमान में हालात यह हैं कि यहां भी %हाथ% को प्रत्याशी ढूंढने पड़ते हैं। 2018 में भाजपा ने इस संभाग की कुल 30 में से 24 सीटें जीती थीं जिसमें इस बार एक सीट का इजाफा हुआ है। शहडोल (3 सीटें), सिंगरौली (3 सीटें) और उमरिया (2 सीटें) जिले कांग्रेस मुक्त हो चुके हैं जबकि सतना जिले में 5-2, रीवा जिले में 7-1 और सीधी जिले में 3-1 से भाजपा ने मजबूत बढ़त बनाई है।

यह वही क्षेत्र है जहां पेशाब कांड के बाद जातिगत मुद्दा अहम हो गया था किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति की नई परिभाषा ने कांग्रेस को चारों खाने चित्त कर दिया। %आप% को संभाग से बड़ी आस थी किंतु उसके हाथ भी कुछ नहीं आया। चुरहट से जरूर स्व. अर्जुन सिंह के पुत्र अजय सिंह %राहुल भैया% चुनाव जीते हैं किंतु वे पार्टी को यहां फिर से कैसे मजबूत करेंगे, यह बड़ा प्रश्न है।

2018 में महाकोशल संभाग ने कांग्रेस को संजीवनी दी थी किंतु इस बार यह संभाग भी भगवामय नजर आया है। कुल 38 सीटों में से 21 सीटों पर भाजपा को जीत मिली है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल को नरसिंहपुर से लड़ाने का भाजपा नेतृत्व का निर्णय संभाग में असर कर गया। जिले की चारों सीटों के अलावा संभाग के कटनी और जबलपुर में भाजपा ने अपना परचम लहराया है। जबलपुर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सुरक्षाकर्मी के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं की मारपीट से ऐसा लग रहा था कि इस बार यहां %कमलदल% में भीतरघात होगा किंतु गृहमंत्री अमित शाह के दौरे ने आपसी लड़ाई समाप्त कर दी। यहां तक कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का नर्मदा माँ की पूजा-अर्चना से प्रारंभ हुआ चुनाव प्रचार भी कांग्रेस को संभाग में एकजुट नहीं रख पाया।

लहंगे के साथ बनवाएं यूनिक डिजाइन के ये ब्लाउज, मिलेगा अट्रैक्टिव लुक

शादियों में लहंगा पहनने का क्रेज कभी खत्म नहीं होता। दुल्हन से लेकर दुल्हन की सहेली और बहनें, लगभग सबको लहंगा पसंद आता है। ऐसे में अगर आप अपने लहंगे के साथ कुछ हटके लुक चाहती हैं तो ब्लाउज के इन अट्रैक्टिव डिजाइन को ट्राई कर सकती हैं। जो ना केवल हर बॉडी टाइप पर जचेंगे बल्कि आपका लुक देख सब तारीफ भी करेंगे। तो अट्रैक्टिव लुक के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस के इन खूबसूरत लहंगा डिजाइन को ट्राई कर सकती हैं।

बटरफ्लाई ब्लाउज डिजाइन

लहंगे के साथ कुछ हटके डिजाइन का ब्लाउज बनवाना चाहती हैं तो आलिया भट्ट का ये बटरफ्लाई डिजाइन का ब्लाउज बनवा सकती हैं। साथ में चाहे तो इसमे नूडल स्ट्राईप की बजाय स्लीव को ऐड करवाएं। ये ब्लाउज डिजाइन अट्रैक्टिव लुक देगा।

डीप वी नेकलाइन

ब्लाउज की ये डीप वी नेकलाइन डिजाइन इन दिनों काफी ज्यादा ट्रेंड में है। जिसे आप भी अपने लहंगे के साथ बनवा सकती हैं। अगर आप इतना डीप नेकलाइन को पहनना पसंद नहीं करती हो इसमे स्किन कलर की लाइनिंग ऐड करवाएं। ये काफी खूबसूरत लुक देगा।

फुल स्लीव संग स्वीटहार्ट नेकलाइन

सर्दियों की शादी में अगर आप ठंड से बचना चाहती हैं तो वेलवेट फैब्रिक के ब्लाउज को भी बनवा सकती हैं। स्वीटहार्ट नेकलाइन और फुल स्लीव ब्लाउज डिजाइन गॉर्जियस लुक देंगे।

बैकलेस चोली ब्लाउज

कृति सेनन की तरह लहंगे के साथ इस तरह की डिजाइन वाले ब्लाउज बनवाएं। फ्रंट से लांग वेस्ट तक डिजाइन और बैक से क्रिसक्रॉस पैटर्न पर लगी डोरी इस ब्लाउज को बेहद ग्लैमरस और अट्रैक्टिव बना सकती है।

ऑफ शोल्डर या पफ स्लीव

लहंगे के साथ दुपट्टे को कैरी करने का इरादा नही है तो ऑफ शोल्डर और पफ स्लीव ब्लाउज बनवाएं। या फिर केवल ऑफ शोल्डर ब्लाउज को भी बनवा सकती है। स्लीव पर फ्रिल डिजाइन का पफ भी काफी अट्रैक्टिव लुक दे सकता है।

तो इस वेडिंग सीजन सहेली की शादी में या मेहंदी से लेकर संगीत के फंक्शन में रेडी होने के लिए लहंगा पहन रही हैं तो इन ब्लाउज की डिजाइन को ट्राई करें। सब तारीफ करेंगे आपके लुक की।

स्किन को साफ करने के लिए लोग महंगे-मंहगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। स्किन केयर का पहला स्टेप चेहरे को साफ करना या फिर फेस वॉश का इस्तेमाल करना होता है। अगर सही तरह से इसे ना पूरा किया जाए तो उतनी चमक नहीं आती। चेहरे तो साफ करने के लिए घर की चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जानिए, फेस वॉश के लिए नेचुरल चीजों का इस्तेमाल कैसे किया जाए।

सुबह के समय इन नेचुरल चीजों की मदद से करें फेस वॉश, चमक जाएगा चेहरा

टमाटर से करें चेहरा वॉश

टमाटर के रस से चेहरा साफ किया जा सकता है। टमाटर में क्लिंजिंग गुण होते हैं, जो त्वचा पर अच्छा असर दिखाते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए एक कटोरी में टमाटर का रस लें और उसे उंगलियों से चेहरे पर मलें। कुछ देर के लिए इसे लगा रहने दें फिर 5 मिनट लगा रहने दें। फिर चेहरे को साफ करें।

चेहार चमकाने के लिए शहद

रूखी-सूखी स्किन से छुटकारा पाने के लिए शहद को चेहरे पर लगाएं। इसके एंटी-ऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण स्किन को सूदिंग इफेक्ट्स भी देते हैं। इसे लगाने के लिए पहले चेहरे को गिला करें और फिर थोड़ा सूखने के बाद शहद को चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें।

कच्चा दूध

चेहरे पर कच्चे दूध को लगाने से फायदा मिलता है। इसे लगाने से डेड स्किन साफ होती है। दूध से चेहरा साफ करने के लिए एक कटोरी में कच्चा दूध लेकर उसमें रूई डुबोएं और चेहरे पर अच्छे से लगाएं। कुछ देर के लिए चेहरे पर कच्चे दूध की मसाज के बाद चेहरे को पानी से धो लें।

तेल और सीरम बालों के लिए क्या है ज्यादा फायदेमंद, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे यह भूल

अगर आपको लगता है हेयर ऑयल और हेयर सीरम एक ही है, तो बता दें कि दोनों में फर्क होता है। तेल जहां स्कैल्प में लगाया जाता है, तो वहीं सीरम बालों में अप्लाई किया जाता है। आइए जानते हैं तेल और हेयर सीरम के बीच का अंतर।

बालों में तेल का इस्तेमाल कई सालों से किया जाता रहा है। तेल बालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। ऑलिव ऑयल से लेकर नारियल तेल तक आप इस्तेमाल कर सकती हैं। आजकल मार्केट में कई तरह के हेयर केयर प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। क्या आप भी अपने बालों में हेयर सीरम का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सीरम और हेयर ऑयल के बीच का फर्क नहीं जानते हैं। आज इस आर्टिकल में हम आपको हेयर सीरम और हेयर ऑयल के बीच का अंतर बताने जा रहे हैं।

तेल और सीरम में फर्क

अगर आपको लगता है कि तेल और सीरम दोनों एक ही चीज हैं। तो बता दें कि तेल और सीरम दोनों एक चीज नहीं है। तेल और सीरम दोनों अलग प्रोडक्ट हैं। सिर के स्कैल्प पर तेल का इस्तेमाल किा जाता है। यह आपके बालों को नरिशमेंट का काम करता है। वहीं हेयर सीरम का उपयोग बालों पर किया जाता है। सीरम का इस्तेमाल करने से बाहरी तत्वों जैसे धूल, गर्म हवा और प्रदूषण आदि से बालों को प्रोटेक्ट करते हैं।

हेयर सीरम लगाने से होने वाले फायदे

हेयर सीरम लगाने से बालों में शाइन आती है। ऐसे में अगर आपके बालों की शाइन खो गई है, तो हेयर सीरम आपको बालों की खोयी हुई चमक वापस लाने में फायदमंद हो सकता है।

स्टाइलिंग टूल्स का इस्तेमाल करने पर और बालों की अच्छे से देखभाल न करने पर बाल ड्राई हो जाते हैं। इसलिए बालों मुलायम करने के लिए हेयर सीरम का इस्तेमाल किया जाता है।

अगर आपके बाल भी फ्रिजी रहते हैं तो बालों में सीरम अप्लाई करना चाहिए। इससे बालों की फ्रिजीनेस कम होगा।

हीट डैमेज से बालों के बचाने के लिए सीरम काम आता है। इसलिए बालों को स्टाइल करने से पहले सीरम का इस्तेमाल करना चाहिए।

जरूरत से ज्यादा बालों के उलझने पर आप हेयर सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीरम अप्लाई करने से बाल कम उलझते हैं।

बाजार में आपको बालों से संबंधित अलग-अलग समस्या के लिए सीरम मिल जाएगा। आप अपने हेयर टाइप के हिसाब से सीरम खरीद सकते हैं।

बालों में तेल अप्लाई करने के फायदे

बालों में तेल लगाने से दोमुहे बालों की समस्या नहीं होती है। इसलिए हेयर केयर रूटीन में आपको तेल जरूर शामिल करना चाहिए।

बता दें कि अगर आप रोजाना हेयर ऑयलिंग करती हैं, तो इससे बालों का रंग काला होता है। बालों को काला करने के लिए नारियल तेल के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है।

तेल बालों की ग्रोथ के लिए भी फायदेमंद होता है। बालों में तेल लगाने से यह बढ़ने लगते हैं।

बालों को हेल्दी और स्ट्रांग बनाए रखने के लिए हेयर ऑयलिंग जरूरी मानी जाती है।

चेहरे पर इन तरीकों से इस्तेमाल करें आंवला, सर्दियों में स्किन करेगी ग्लो

आंवला हर मौसम में खाने की सलाह दी जाती है। इससे सेहत का सुधार होता है और स्किन-बाल भी अच्छे होते हैं। स्किन पर मौजूद जिद्दी से जिद्दी दाग-धब्बे हटाने की बात हो या फिर रंगत निखारने की, आप आंवला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये विटामिन सी और एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, यही वजह है कि कई लोग इसे रोजाना खाना पसंद करते हैं। घर पर कई देसी तरीकों से आप आंवला का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। यहां जानिए अलग-अलग तरीकों से आंवला का इस्तेमाल कैसे करें।

1) अगर आपको पिंपल्स की समस्या है, तो आप अपने स्किन केयर रूटीन में आंवले का फेस पैक जरूर शामिल करें। इस फेस पैक बनाने के लिए बाउल में 2 चम्मच आंवला पाउडर में दही और गुलाब जल मिला लें। फिर इसे अपने चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। 15 मिनट बाद फेस को पानी से साफ करें।

2) बढ़ती उम्र के साथ बढ़ रही स्किन प्रॉब्लम से निपटने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला का इस्तेमाल फेस मसाज के लिए भी किया जा सकता है। फेस मसाज के लिए 1 चम्मच आंवले के जूस में 1 चम्मच बादाम का तेल मिक्स कर लें। फिर सुबह या फिर रात में सोने से पहले इस मिक्स से अपने फेस की अच्छी तरह मसाज करें। इसे चेहरे पर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर बाद में फेस को साफ करें।

3) झुर्रियां और ब्लैकहेड्स की समस्या से बचाव के लिए रोजाना अपनी स्किन को स्क्रब करें। फिर आंवला से स्क्रब बनाएं, इसके लिए दो कच्चे आंवले को पीसकर पेस्ट बना लें। फिर इसमें आधा चम्मच शहद मिलाएं। दोनों को मिक्स करने के बाद 1 चम्मच ग्रीन टी मिक्स करें। फिर इस मिक्स से फेस को अच्छी तरह स्क्रब करें। रंगत निखारने के लिए ये बेस्ट है।

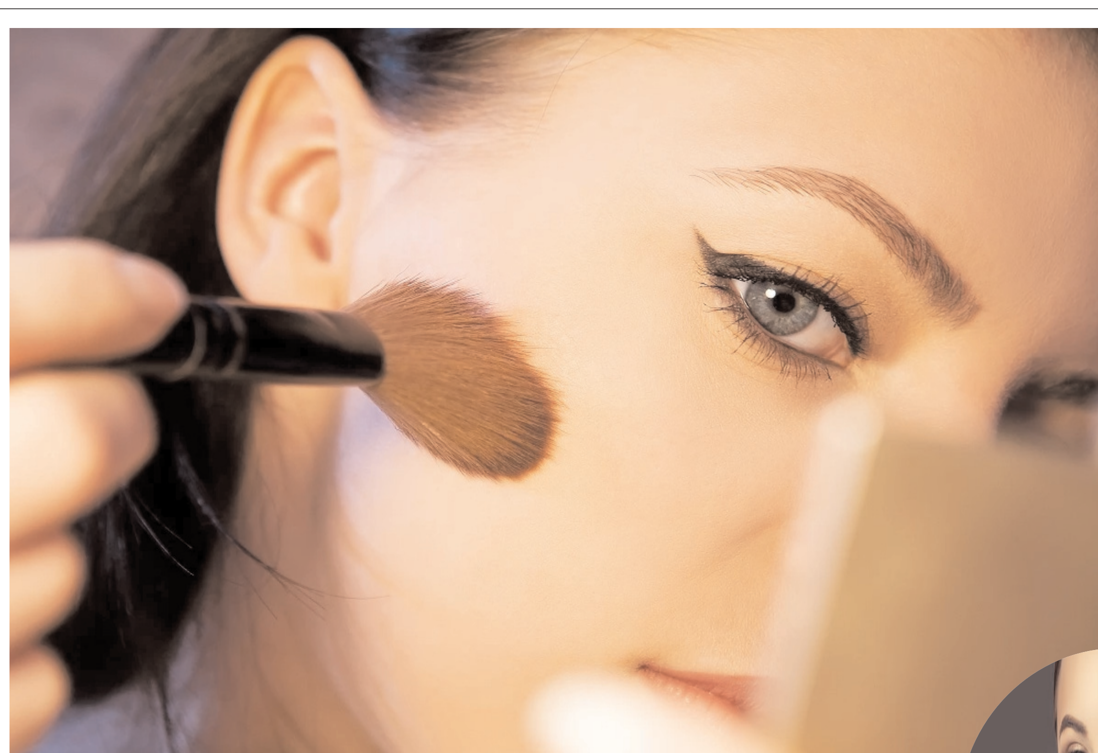

बढ़ती उम्र के साथ भी दिखना चाहती हैं जवां, तो मेकअप करते समय न करें

मेकअप हर महिला के जीवन में काफी अहमियत रखता है। मेकअप से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ ही मेकअप करने में भी कुछ बदलाव होते हैं। ऐसे में इन टिप्स का जरूर ध्यान देना चाहिए।

हर महिला की जिंदगी में मेकअप काफी अहमियत रखता है। महिलाओं का आत्मविश्वास मेकअप करने से कई गुना बढ़ जाता है। बता दें कि एक समय महिलाएं व लड़कियां मेकअप से दूर रहती थीं। लेकिन समय बदलने के साथ ही महिलाएं न सिर्फ शादी-बारात बल्कि आने-जाने में भी मेकअप का इस्तेमाल करती हैं। क्योंकि मेकअप से महिलाएं काफी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि एक उम्र के बाद मेकअप करने के दौरान एक छोटी सी गलती आपको अजीब लुक दे सकता है। इसलिए मेकअप करने के दौरान उम्र का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वहीं मेकअप करने से पहले आपको अपने स्किन टेक्सचर के बारे में पता होना जरूरी होता है। इससे मेकअप करने में आसानी होती है। अगर आप बिना अपना स्किन टेक्सचर जाने बिना ही मेकअप अप्लाई करती हैं तो इसका सीधा असर आपकी त्वचा पर पड़ता है। इस आर्टिकल में हम आपको बढ़ती उम्र के साथ मेकअप करने के दौरान ध्यान रखने वाली कुछ बातों को बताने जा रहे हैं।

बेस अच्छे से करें ब्लेंड

बढ़ती उम्र के साथ ही चेहरे पर झुर्रियां आने लगती हैं। इसलिए बेस लगाते समय इसे अच्छे से ब्लेंड करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो फेस पर झुर्रियों के कारण मेकअप की लाइनें बन जाएंगी। वहीं बेस को अच्छे से ब्लेंड नहीं किए जाने पर मेकअप फेस पर एक ही जगह जमा हो जाता है।

ज्यादा प्रोडक्ट न करें इस्तेमाल

बढ़ती उम्र के साथ अपने फेस पर ज्यादा प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप चेहरे पर ज्यादा प्रोडक्ट या क्रीम आदि का इस्तेमाल करती हैं तो फेस पर इसकी लेयर्स और स्किन नकली लगने लगती है। यह देखने में काफी अजीब लगता है।

रंगों का जरूर रखें ध्यान

स्किन पर बेस और आई मेकअप करते समय डार्क या डीप शेड के कलर्स भूलकर भी नहीं चुनने चाहिए। क्योंकि एक उम्र के बाद त्वचा ढीली होने लगती है। जिससे आपका मेकअप काफी अजीब दिखने लगता है।

ग्लिटर को रखें दूर

बढती उम्र के साथ ही ग्लिटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ ही न सिर्फ चेहरे बल्कि आंखों के ऊपर भी झुर्रियां आने लगती हैं। ऐसे में अगर आप आई मेकअप में ग्लिटर का इस्तेमाल करती हैं तो यह आपके लुक को बेकार कर सकता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

17 दिसंबर को दो दिवसीय दौरे पर काशी आएंगे पीएम मोदी

वाराणसी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर को दो दिवसीय दौरे पर काशी आएंगे। इसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की ओर से काशी में उनके भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। काशी प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से तैयार हुई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही पीएम काशीवासियों से संवाद स्थापित कर आगामी लोकसभा चुनाव के प्रचार का शंखनाद करेंगे। प्रधानमंत्री के दो दिवसीय दौरे को लेकर जिला प्रशासन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री 17 दिसंबर की दोपहर काशी आएंगे। नदेसर स्थित कटिंग मेमोरियल ग्राउंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे और प्रतिभागियों से संवाद करेंगे।

फडणवीस के चिट्ठी पर अजित पवार ने दी प्रतिक्रिया

मुंबई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने साथी डिप्टी सीएम अजित पवार को नवाब मलिक को सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल करने पर विरोध करते हुए चिट्ठी लिखी है। राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि वह पहले नवाब मलिक के पक्ष को जानने के बाद अपना जवाब देंगे। अजित पवार ने कहा, मुझे फडणवीस का चिट्ठी मिला। मैं नवाब मलिक के आधिकारिक पक्ष को जानने के बाद अपनी बात रखूंगा। विधानसभा में कौन कहां बैठेगा, यह मैं तय नहीं करता हूं। स्पीकर इसे तय करते हैं। नवाब मलिक के अजित पवार गुट में शामिल होने पर विवाद महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। अजित पवार गुट के राकांपा नेता अमोल मिटकारी ने कहा, नवाब मलिक पार्टी के प्रवक्ता और एक वरिष्ठ नेता रहे हैं। अब वह खुद अपना पक्ष स्पष्ट करेंगे। उन्होंने कहा, बैठने की व्यवस्था सरकार की तरफ की गई है।

कांग्रेस की छह गारंटी को पूरा करना रेवंत रेड्डी के लिए चुनौती

हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद रेवंत रेड्डी के समक्ष अपने वादों को पूरा करने की बड़ी चुनौती हैं। शपथ लेने के कुछ देर बाद ही अपने अभियान का एक प्रमुख वादा पूरा करते हुए आधिकारिक आवास के सामने लगे लोहे के बैरिकेड हटा दिए। रेड्डी और उनके मंत्रिमंडल को अब खस्ताहाल खजाने का प्रबंधन करने और कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनावों के दौरान की गई छह गारंटियों को पूरा करने की कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कहा जाता है कि छह गारंटियों को उजागर करने वाला कांग्रेस का मजबूत अभियान पार्टी की जीत के कारणों में से एक था। हालाँकि, उन्हें पूरा करने के लिए धन ढूँढना एक कठिन कार्य होगा। छह में सबसे आकर्षक है तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा। इन छह गारंटियों को महालक्ष्मी, रयथु भरोसा, गृह ज्योति, इंदिरम्मा इंदलु, युवा विकासम और चेयुथा के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

लालदुहोमा ने मिजोरम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

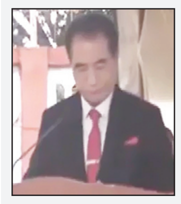

आइजोल। ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) के नेता लालदुहोमा ने शुक्रवार को मिजोरम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मिजोरम के राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति ने राजभवन परिसर में लालदुहोमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे आइजोल में हुआ। मिजोरम में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए हाल ही में घोषित परिणामों में, जेडपीएम ने पूर्वोत्तर भारत के राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए 40 में से 27 सीटें जीतीं। मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 में, लालदुहोमा को सेरछिप निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुना गया था। उन्हें कुल 8314 वोट मिले जो दूसरे सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले मिज़ो नेशनल फ्रंट के जे. माल्सावमज़ुआला वानचावंग से 2982 अधिक थे। 74 वर्षीय लालदुहोमा पूर्व भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी हैं। उन्हें 1977 में आईपीएस के लिए चुना गया था।

तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर अस्पताल में भर्ती

हैदराबाद। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केसीआर बीती रात एर्रावल्ली स्थित अपने फार्महाउस में गिर गए थे। जानकारी के मुताबिक, केसीआर बीती रात फिसलकर गिर गए थे। इसके बाद उन्हें देर रात हैदराबाद के यशोदा अस्पताल ले जाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री पिछले तीन दिनों से अपने घर पर लोगों से मिल रहे थे। डॉक्टर्स का मानना है कि के.चंद्रशेखर राव को गिरने के बाद कूल्हे में फ्रैक्चर हुआ होगा। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें ठीक होने में छह से आठ हफ्ते का समय लग सकता है। तेलंगाना बीआरएस एमएलसी के कविता ने ट्वीट कर बताया कि बीआरएस सुप्रीमो को मामूली चोट लगी है और फिलहाल वह अस्पताल में विशेषज्ञों की देखरेख में हैं। लोगों के समर्थन और शुभकामनाओं से पिताजी जल्द ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।

लोकसभा चुनाव 2024 जीतने को आश्वस्त हैं प्रधानमंत्री! देहरादून में बोले-

मेरे तीसरे टर्म में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा भारत : मोदी

देहरादून। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी लोकसभा चुवाओं से पहले बड़ा बयान दिया हैं। उन्होंने अपने तीसरे टर्म को लेकर बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने केंद्र में बीजेपी सरकार के तीसरे टर्म की बात कहकर तीन राज्यों में हार से कराह रहे विपक्ष के जख्मों पर नमक छिड़क दिया है।

देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोपहर 12.23 से 12.55 तक अपना भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पहाड़ी टोपी में नजर आए। वहीं इस मौके पर उन्होंने उत्तराखंड की धरती को देवभूमि बताया और कहा कि वह इस धरती के हमेशा ऋणी रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि इस धरती के लिए उन्हें जब भी कुछ करने का मौका मिलेगा वह उनके लिए सौभाग्य होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में एक बड़ा बयान दिया है। देश में लगातार विकास और पॉलिसी लेवल पर सुधार पर बोलते हुए सभी निवेशकों का आह्वान किया कि उत्तराखंड में अधिक से अधिक निवेश करें। इस दौरान पीएम मोदी ने ऐलान किया कि उनके तीसरे टर्म में भारत देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। यानी साफ है कि पीएम मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने को लेकर आश्वस्त हैं।

आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के जल्द होने हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सियासी गलियारों में चर्चा में रहने वाला है। हाल ही में पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद तीन राज्यों में सरकार बनाने जा रही बीजेपी के प्रदर्शन से खुश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान दिखाता है कि वह पूरे कॉन्फिडेंस में हैं। आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने अपने तीसरे टर्म की घोषणा कर दी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में आकर मन धन्य हो जाता है। कुछ वर्ष पहले जब मैं बाबा केदार के दर्शन के लिए निकला था, तो अचानक मेरे मुंह से निकला था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। मुझे खुशी है कि अपने उस कथन को मैं लगातार चरितार्थ होते हुए देख रहा हूं। उन्होंने कहा कि बीते दिनों उत्तरकाशी में टनल से हमारे श्रमिक भाईयों को सुरक्षित निकालने का जो सफल अभियान चला, उसके लिए मैं राज्य सरकार समेत सभी का अभिनंदन करता हूं।

मोदी ने कहा कि सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि निश्चित रूप से आपके लिए बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। आज भारत विकास भी और विरासत भी के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आपको आज देश में नीति-संचालित शासन दिखेगी, आपको आज राजनीतिक स्थिरता के लिए देशवासियों का मजबूत आग्रह दिखेगा। उन्होंने कहा कि आकांक्षी भारत आज अस्थिरता नहीं चाहता, वह आज स्थिर सरकार चाहता है। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में हमने ये देखा है और उत्तराखंड के लोगों ने इसे पहले ही करके दिखाया है।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत और भारतीयों को दुनिया जिस उम्मीद और सम्मान से देख रही है, उसे हर भारतीय एक दायित्व के रूप में ले रहा है। हर देशवासी को लगता है कि विकसित भारत का निर्माण उसकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सरकार अपनी तरफ से जमीनी सच्चाई को समझते हुए यहां तेजी से काम कर रही है और भारत सरकार की योजनाओं को, हमारे विजन को भी उतनी ही तेजी से जमीन पर उतारती है। मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों की अप्रोच थी कि जो इलाके सीमा पर हैं, उनको ऐसे रखा जाए कि एक्सेसे कम हो। डबल इंजन की सरकार ने इस सोच को भी बदला है। हम सीमावर्ती गांवों को लास्ट विलेज नहीं, बल्कि देश के फर्स्ट विलेज के रूप में विकसित करने में जुटे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत को देखने के लिए भारतीयों और विदेशियों दोनों में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है। हम पूरे देश में थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट तैयार कर रहे हैं। कोशिश ये है? कि भारत के नेचर और हेरिटेज दोनों से ही दुनिया को परिचित कराया जाए। इस अभियान में उत्तराखंड, टूरिज्म का एक सशक्त ब्रांड बनकर उभरने वाला है। उन्होंने कहा कि मेरा एक संकल्प है, आने वाले कुछ समय में इस देश में 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने के लिए मैंने लखपति दीदी अभियान चलाया है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड से 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने का काम तेजी से पूरा हो जाएगा।

मप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पर्यवेक्षकों के नाम का भाजपा ने किया ऐलान

नईदिल्ली। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपने विधायक दल के नेताओं के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों के नामों की घोषणा कर दी। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम होंगे।

भाजपा पर्यवेक्षक की लिस्ट- 1-राजस्थान: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे। 2-मध्य प्रदेश: हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण, आशा लाकड़ा। 3- छत्तीसगढ़: केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम।

भाजपा ने राजस्थान में विधायक दल के नेता के चयन के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। मध्य प्रदेश में विधायक दल के नेता के चयन के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पार्टी संसदीय बोर्ड के सदस्य के. लक्ष्मण और राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों नवनिर्वाचित विधायकों की बैठकों के लिए संबंधित राज्यों की यात्रा करेंगे, जहां भविष्य के मुख्यमंत्रियों के नाम घोषित करेंगे। पार्टी तीनों मुख्यमंत्रियों को चुनने में सामाजिक, क्षेत्रीय, शासन और संगठनात्मक हितों को ध्यान में रखेगी।

तीन राज्यों के नेता गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं देते हुए कहा कि इस तरह की बैठकें नियमित होती हैं। उन्होंने कहा, राज्य के कई नेता हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से मिल रहे हैं। केवल तीन मुख्यमंत्री हो सकते हैं। किसी को भी इसे ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि संभावितों में वे सांसद भी शामिल हैं जिन्होंने संसद से इस्तीफा दे दिया है और शिष्टाचार के तौर पर राष्ट्रीय नेताओं से मिल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राजस्थान के बाबा बालकनाथ ने शाह से मुलाकात की। दोनों ने अपने-अपने राज्यों की विधानसभा का सदस्य चुने जाने के बाद लोकसभा की सदस्यता छोड़ दी।

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी दिल्ली में हैं। पिछले दिनों उन्होंने कई नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की है। सूत्रों ने बताया कि वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर सकती हैं। तोमर, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल और शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के संभावित विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

चौहान की तरह पटेल भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। पटेल और तोमर भाजपा के उन 12 सांसदों में शामिल हैं जो विधानसभा सदस्य चुने गए हैं और उन्होंने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, संसद की सदस्यता से इस्तीफा देने वाली गोमती साय और प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री लता उसेंडी भी शामिल हैं।

साव ओबीसी समुदाय से हैं वहीं साय और उसेंडी अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। सामाजिक पृष्ठभूमि, छवि और अपेक्षाकृत युवा प्रोफ़ाइल के कारण राज्य के शीर्ष पद के लिए इन नेताओं को मजबूत दावेदारों के रूप में देखा जा रहा है।

खेल
प्रमुख समाचार

द. अफ्रीका के खिलाफ तीनों फॉर्मेट में तीन नए भारतीय कप्तान

नईदिल्ली। दक्षिण अफ्रीका के दौरे के दौरान भारतीय टीम वहां तीन टी20, तीन वनडे और दो टेस्ट मुकाबले खेलेगी। दक्षिण अफ्रीका के दौरे के दौरान भारतीय टीम की तीनों फॉर्मेट में तीन अलग कप्तान अपना दांव खेलेंगे। टी20 टीम की कमान भारतीय टीम के घातक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव संभाल रहे हैं। वहीं वनडे सीरीज की कमान केएल राहुल संभाल रहे हैं। जबकि टेस्ट टीम की कमान रोहित शर्मा को सौंपी गई है। वहीं मोहम्मद शमी फिलहाल चिकित्सा उपचार से गुजर रहे हैं और उनकी उपलब्धता फिटनेस पर निर्भर है। वनडे विश्व कप मुकाबले के बाद फिर एक बार हम सभी रोहित शर्मा को खेलते हुए पाएंगे। एक साल से अधिक समय से रोहित शर्मा अपने आप को टी20 फॉर्मेट से दूर रखे हुए हैं। वनडे विश्व कप 2023 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस कदम को उठाया था। जिसके बाद से अभी तक उन्होंने एक भी टी20 मुकाबला नहीं खेला है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के समय में काफी अंतर है। भारत, दक्षिण अफ्रीका से 3.30 घंटे आगे चलता है। जब भारत में सुबह के 10 बज रहे होते हैं, तो साउथ अफ्रीका में उस समय सवेरे के 6.30 बजते हैं। ऐसे में साउथ अफ्रीका टूर पर मैचों के समय में भी बड़ा अंतर रहने वाला है।

साउथ अफ्रीका दौरे का शेड्यूल

10 दिसंबर, पहला टी20, डरबन, शाम 7.30 बजे
12को दूसरा टी20, पोर्ट एलिजाबेथ, रात 8.30 बजे
14 को तीसरा टी20, जोहानिसबर्ग, रात 8.30 बजे
17को पहला वनडे, जोहानिसबर्ग, दोपहर 1.30 बजे
19 को, दूसरा वनडे, पोर्ट एलिजाबेथ, शाम 4.30 बजे।
21 को, तीसरा वनडे, पार्ल, शाम 4.30 बजे।
26 से 30 दिसंबर, पहला टेस्ट, सेंचुरियन, दोपहर 1.30 बजे।
3 से 7 जनवरी, दूसरा टेस्ट, जोहानिसबर्ग, दोपहर 1.30 बजे।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 304 अंक चढ़ा, निफ्टी पहली बार 21 हजार के पार

नईदिल्ली। आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के बाद घरेलू शेयर बाजारों में जोरदार उछाल आया। आज के कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 304 अंक मजबूत हुआ। वहीं, निफ्टी में भी 68 अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे पहले मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू से उत्साहित होकर दोपहर के कारोबार में निफ्टी 50 बेंचमार्क ने पहली बार 21,000 का आंकड़ा पार किया। निफ्टी 50 को 20,000 से 21,000 अंक पार करने में 60 कारोबारी सत्र लगे।निफ्टी 50 ने इसी साल 11 सितंबर को पहली बार 20 हजार के स्तर को छूआ था। बीएसई सेंसेक्स में भी बढ़त रही और यह 300 अंक उछलकर 69,888 के नए ऑलटाइम हाई पर पहुंच गया था। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 303.91 अंक यानी 0.44 फीसदी की बढ़त के साथ 69,825.60 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज 69,506.12 और 69,893.80 के रेंज में कारोबार हुआ।

रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 5वीं बार 6.5% पर रखा स्थिर

नईदिल्ली। रिजर्व बैंक का रेपो रेट पर उदार रुख अपनाया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से पॉलिसी रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। नतीजतन, स्थायी जमा सुविधा दर 6.25% और सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर 6.75 पर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि चालू वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7% अनुमानित है-तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6% हो सकती है। 2024-25 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.7%, दूसरी तिमाही के लिए 6.5% और तीसरी तिमाही के लिए 6.4% अनुमानित है। जोखिम समान रूप से संतुलित हैं। रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक समीक्षा नीति बैठक का आयोजन छह और सात सितंबर को किया गया है।

सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगाया प्रतिबंध

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश में प्याज की बढ़ती मांग और बढ़ती कीमतों के चलते सरकार ने यह फैसला किया है। बता दें कि फिलहाल यह प्रतिबंध अगले साल मार्च तक लगाया गया है। विदेशी व्यापार के डायरेक्टोरेट जनरल की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 31 मार्च 2024 तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि डीजीएफटी के नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि देशों की मांग पर केंद्र सरकार की इजाजत से प्याज का निर्यात किया जा सकेगा। बता दें कि देश में अभी प्याज खुदरा कीमत में 60 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रही है। अगस्त में सरकार ने प्याज के निर्यात को कम करने के लिए इस पर 40 प्रतिशत एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी। यह आदेश 31 दिसंबर 2023 तक के लिए था। हालांकि केंद्र सरकार ने बंगलूरू रोज किस्म की प्याज को एक्सपोर्ट ड्यूटी से मुक्त रखा था।

कीमतों पर काबू के लिए गेहूं भंडारण सीमा घटाई

नईदिल्ली। सरकार ने गेहूं की जमाखोरी रोकने और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करण फर्मों के लिए गेहूं का भंडार (स्टॉक) रखने के मानदंडों को सख्त कर दिया। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने यहां संवाददाताओं से कहा कि व्यापारियों एवं थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं भंडारण की सीमा 2,000 टन से घटाकर 1,000 टन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक खुदरा विक्रेता के लिए भंडारण सीमा 10 टन के बजाय पांच टन, बड़े खुदरा विक्रेताओं के प्रत्येक डिपो के लिए पांच टन और उनके सभी डिपो के लिए यह सीमा कुल मिलाकर 1,000 टन होगी। उन्होंने कहा कि गेहूं का प्रसंस्करण करने वालीं कंपनी वित्त वर्ष 2023-24 के बाकी महीनों के अनुपात में मासिक स्थापित क्षमता का 70 प्रतिशत रख सकती हैं।

एलआईसी और एसबीआई पर झूठ फैलाने वाला विपक्ष अब सच्चाई दिखाएगा?

नीरज कुमार दुबे

भारतीय जीवन बीमा निगम यानि एलआईसी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बीमा कंपनी बन गयी है। एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार, एलआईसी का रिजर्व 503.7 अरब डॉलर रहा। रिपोर्ट के अनुसार इस सूची में पहले नंबर पर जर्मनी की एलियांज एसई, दूसरे नंबर पर चाइना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और तीसरे नंबर पर निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी शामिल हैं। एलआईसी इस सूची में एकमात्र भारतीय कंपनी है।

इसके अलावा, भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक के शुद्ध लाभ में 8 प्रतिशत की सालाना वृद्धि हुई है। हम आपको बता दें कि इस वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में भारतीय स्टेट बैंक ने 14,330 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की है।

आप सोच रहे होंगे कि यह दोनों आंकड़े हम आपको क्यों बता रहे हैं? दरअसल हम यह आंकड़े आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि विपक्ष ने इस साल की शुरुआत में संसद के बजट सत्र के दौरान मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि सरकार ने एसबीआई और एलआईसी का पैसा उद्योगपति गौतम अडाणी को दे दिया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने आरोप लगाया था कि आम निवेशकों और पॉलिसी धारकों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। इसके लिए कांग्रेस ने देशभर में एलआईसी और एसबीआई कार्यालयों पर मार्च और विरोध प्रदर्शन भी किया था। यहां सवाल यह उठता है कि उस समय एलआईसी, एसबीआई और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों द्वारा बार-बार दिये जा रहे स्पष्टीकरण को खारिज करता रहा विपक्ष क्या आज जनता को अर्थव्यवस्था का सच बताने की हिम्मत दिखायेगा? हम

आपको यह भी बता दें कि यह विपक्ष के नेता बार-बार ईडी पर जो सवाल उठाते हैं यह उस ईडी की छापेमारियों का ही कमाल है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपने 15 हजार करोड़ रुपए उन भ्रष्टाचारियों और भगोड़ों से वापिस मिल पाये हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बताया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन रोकथाम कानून के तहत कार्रवाई करते हुए 15,186.64 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है तथा इनमें से लगभग सभी राशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वापस लौटा दी गई है। यही नहीं, विपक्ष जोकि बार-बार सरकार पर बैंकों को बर्बाद करने का आरोप लगाता है उसे यह आंकड़ा भी देखना चाहिए कि पिछले दो वित्त वर्ष में, वाणिज्यिक बैंकों में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनएपी) खातों की संख्या 2.19 करोड़ से घटकर 2.06 करोड़ हो गई है, जो 6.2 प्रतिशत की कमी स्पष्ट करती है। इसी प्रकार, इस अवधि के दौरान ऐसे खातों का कुल बकाया (सकल एनपीए) 7.41 लाख करोड़ रुपये से घटकर 5.72 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो 22.9 प्रतिशत की गिरावट दिखाता है। यही नहीं, विपक्ष के जो आर्थिक सलाहकार भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 5 से साढ़े पांच प्रतिशत के बीच रहने की भविष्यवाणियां करते फिरते थे वह भी आश्चर्यचकित हैं कि कैसे उनके सभी अनुमान धरे के धरे रह गये हैं और भारत अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और उसने पिछली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत दर्ज की है। इसके बाद एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने ऐलान कर दिया कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) का भी अनुमान है कि भारत 2027-28 तक 5,000 अरब डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। इसके अलावा, विपक्षी नेता भले देश की अर्थव्यवस्था के विकास के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हों लेकिन भारत के करीब 94 प्रतिशत मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) देश के आर्थिक भविष्य को लेकर आशावादी हैं। इसलिए विपक्ष को कम से काम आर्थिक मुद्दों पर भ्रम और भय फैलाने की राजनीति से बचना चाहिए।

13 को छग के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह

पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई दिग्गज होंगे शामिल

रविवार को आएंगे भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक, लेंगे विधायकों की बैठक

रायपुर. छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री का इंतजार सभी को है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा. शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, पार्टी के प्रदेश प्रभारी सहित कई दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं. बता दें कि विधायक दल का नेता चुनने भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक टीम के सदस्य 10 दिसंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे. 11 दिसंबर को विधायक दल की बैंठक में सीएम का ऐलान किया जाएगा. इसके बाद 13 दिसंबर को नव नियुक्त मुख्यमंत्री शपथ लेंगे.

केंद्र सरकार में जनजातीय मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे अर्जुन मुंडा को भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ का पर्यवेक्षक बनाया है. केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग एवं आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल भी पर्यवेक्षकों के पैनल में शामिल हैं. सोनोवाल असम के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं. इस लिहाज से भी उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है. संगठन का लंबा अनुभव रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार को भी पार्टी ने पर्यवेक्षक का दायित्व सौंपा है. वे हरियाणा से राज्यसभा सांसद भी रहे हैं. भाजपा संगठन के अलग-अलग पदों पर रह चुके हैं.

गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रह्लाद सिंह पटेल का इस्तीफा गुरुवार को स्वीकार कर लिया था। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को नरेंद्र सिंह तोमर की जगह कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बताते है कि नए मंत्रालय के कामकाज को लेकर कुछ महत्वपुर्ण बैठकें शनिवार को होनी है, जिसके बाद वे रविवार रायपुर पहुंचेंगे।

मुख्यमंत्री की दौड़ में चल रहे इन नेताओं के नाम

छत्तीसगढ़ में सीएम पद को लेकर कई नामों पर चर्चा है. छत्तीसगढ़ में जिन नामों की चर्चा खूब रही है, वो विष्णुदेव साय, गोमती साय, रेणुका सिंह, डॉक्टर रमन सिंह, ओपी चौधरी और अरुण साव हैं. इन सबके अलावा महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस और आरएसएस से जुड़े नेता डॉ. पूर्णेन्दु सक्सेना का नाम भी सीएम की दौड़ में शामिल हो गया है. अब बीजेपी आलाकमान ही तय करेगा कि इन सभी में से किसे सीएम की कुर्सी में बिठाया जाएगा.

जयसिंह अग्रवाल ने अपनी ही सरकार पर साधा निशाना, बोले-

प्रदेश के मुखिया हार की असली वजह, मंत्रियों को नहीं मिला पावर

रायपुर/कोरबा। कांग्रेस की सरकार जाने के बाद अब समीक्षा की जा रही है, इसी बीच कोरबा जिले में भी शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी ने हार को लेकर मंथन किया। इस दौरान कोरबा विधायक और सरकार में राजस्व मंत्री रहे जयसिंह अग्रवाल ने दनादन कई आरोप मढ़ दिए। उन्होंने सीधे-सीधे प्रदेश के मुखिया को हार की असली वजह बता दिया। जयसिंह ने कहा कि जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। जिन्होंने पांच साल सरकार की अगुवाई की उनकी गलत नीतियों और तानाशाही रवैया ही हार का असली कारण है। जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि कोरबा जिले में चुन चुनकर ऐसे अधिकारियों को भेजा गया। जो भ्रष्टाचार में

लिप्त रहे। चलते हुए विकास कार्य को बीच में रोक दिया गया। जिससे कांग्रेस की छवि खराब हुई। जिले में कांग्रेस डैमेज हुई। कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए। चारों ओर नाराजगी फैल गई। जिसका परिणाम यह रहा की पूरे राज्य में ही सत्ता से कांग्रेस बेदखल हो गई।

छग में कांग्रेस के 15 सवर्ण उम्मीदवारों में से 13 प्रत्याशी चुनाव हारे

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के कांग्रेस के 15 उम्मीदवारों में से 13 को हार का सामना करना पड़ा। जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने ऊंची जातियों के 18 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे और जिनमें से 16 विजयी हुए। चुनाव विशेषज्ञों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना और अन्य पिछड़ा वर्ग को लुभाने की कांग्रेस की कोशिश ने ऊंची जातियों के साथ-साथ अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों की संभावनाओं को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि संभवत: अधिकतर मतदाताओं को भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार की ओबीसी समर्थक राजनीति रास नहीं आई।

पूर्व विधायक के बयान को लेकर धरमलाल का पलटवार, बृहस्पत सिंह को बताया दुखी

रायपुर. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। हाल ही में कांग्रेस के पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह का ने टीएस सिंह देव और प्रभारी सैलजा को लेकर सवाल किया था। जिसके बाद उनके इस बयान को लेकर भाजपा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का बड़ा बयान सामने आया है।

धरमलाल कौशिक ने कहा कि बृहस्पत सिंह व्यथित और दुखी हैं। कांग्रेस शूरू से अंतरकलह से ग्रस्त है। विकास के बजाय वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम है, कांग्रेस पराजित हुई है। उन्होंने आगे कहा कि अमरजीत भगत आज कह रहे हैं कि हम बहुत पहले से बोलते आए हैं कांग्रेसी ही कांग्रेस को निपटाने में लगे हुए है। यही कारण है आज कांग्रेस की ये दुर्गति हुई है। कांग्रेस चारों खाने से चित्त हो गई है।

धरमलाल कौशिक ने आगे कहा कि भाजपा अपने मुद्दे लेकर जनता के पास गई। जनता ने कांग्रेस को रिजेक्ट किया और भाजपा को जनादेश दिया। सीएम चेहररे को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा सीएम कौन होगा। पर्यवेक्षक इसे लेकर चर्चा करेंगे। मैं सीएम के रेस की बात नहीं करता। पार्टी जो भी? जिम्मेदारी देती है हम उसका निर्वहन करते हैं। नए कैबिनेट में पूरे प्रदेश की भूमिका होगी। पूरे प्रदेश ने हमें चौतरफा जनादेश दिया है।

उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई के साथ अधिकारियों ने बता दिया है कि सरकार बदल गई और अधिकारी भी बदल गए है। सांसद महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर कहा, लोकतंत्र में जनता को अपना जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि को जनता के हित में प्रश्न उठाने का अधिकार है, लेकिन इसका दुरुपयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से इस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। जो कार्रवाई हुई है वह जायज है।

कलेक्टर ने ली जल जीवन मिशन की बैठक

लक्षित प्रत्येक घर में मार्च अंत तक पेयजल पहुंचाने के दिए निर्देश गुणवत्ता के साथ ना हो समझौताः डॉ भुरे

रायपुर। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने आज कलेक्टोरेट परिसर स्थित कलेक्टर सभाकक्ष में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य हितग्राहियों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करना है। इसे प्राथमिकता से पूर्ण करें। यह ध्यान रखें की गुणवत्ता में किसी प्रकार की समझौता ना किया जाए। कनेक्शन देने के बाद पेयजल की आपूर्ति होना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर ने कहा कि जिले में एक लाख 90 हजार घरेलू नल कनेक्शन स्वीकृत किए गए है। इसमें से एक लाख 64 हजार 93 घरेलू कनेक्शन प्रदाय किए गए हैं। कुल 26 हजार कनेक्शन बाकी है। जिसे फरवरी के अंत तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। 212 गांव में कार्य पूर्ण हो गए है, बचे ग्रामों में 31 मार्च तक शतप्रतिशत कार्य पूर्ण करें। डॉ भुरे ने कहा कि घरेलू कनेक्शन देने के लिए सड़कों की कटिंग की गई है, उसकी गुणवत्ता पूर्वक मरम्मत की जाए। साथ ही हितग्राहियों को जागरूक करें कि जल का सदुपयोग हो और नलों में पंप का उपयोग ना करें। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अबिनाश मिश्रा ने कहा कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी जनपद पंचायत के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें और किसी प्रकार की समस्या आने पर उन्हे सूचित करें। यह ध्यान रखें की नलों में पेयजल की आपूर्ति सतत् और उचित ढंग से हो। स्कूलों और आंगनबाडियों में यथासंभव कनेक्शन प्रदान करें। इस अवसर पर कार्यपालन अभियंता श्री फिलिप एक्का सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

बारहवीं के विद्यार्थियों की संख्या में आई कमी

रायपुर. पिछले साल की तुलना में कक्षा बारहवीं के विद्यार्थियों की संख्या में कमी आई है. पिछले साल की तुलना में कक्षा बारहवीं के विद्यार्थियों की संख्या में कमी आई है. इस साल 4081 स्कूलों में कक्षा 12वीं में 2,54,869 विद्यार्थी पंजीकृत किए गए हैं. हालांकि, लेट फ़ीस के साथ पंजीयन करने का मौक़ा दिया गया था, उसके बाद भी आंकड़ों में कमी देखी गई है. माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव वी के गोयल ने बताया, कोरोना से डारेक्ट प्रमोशन में विद्यार्थी 12वीं में पहुंचे थे, इसलिए संख्या ज़्यादा थी. इस साल पिछले साल की तुलना में कम संख्या है. कक्षा 11वीं में 4097 स्कूलों में 2,54,843 विद्यार्थी हुए पंजीकृत किए गए. वहीं कक्षा दसवीं में 6682 स्कूलों में 3,42,499 विद्यार्थी पंजीकृत हुए.

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

प्रधानमंत्री मोदी 11 दिसंबर को विकसित भारत @ 2047 आइडियास पोर्टल का शुभारंभ करेंगे

राजभवन में होगा कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को विकसित भारत @2047 आइडियास पोर्टल का शुभारंभ करेंगे और वर्चुअल संबोधन देंगे। इस कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण राजभवन में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के संबोधन के पश्चात राजभवन में राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन की अध्यक्षता में एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी जिसमें राज्य के सभी शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण उपस्थित रहेंगे।

इस संबंध में आज नीति आयोग नई दिल्ली द्वारा वीडियो कॉफ्रेंसिंग आयोजित कर कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में राज्यपाल के सचिव श्री अमृत खलखो, उप सचिव श्री दीपक अग्रवाल उपस्थित थे। 11 दिसंबर को होने वाली कार्यशाला में विकसित भारत, सशक्त भारतीय, सम्पन्न और टिकाऊ अर्थव्यवस्था, सुशासन एवं सुरक्षा, विश्व में भारत आदि विषयों पर चर्चा की जायेगी।

1998 बैच के आईपीएस अमित कुमार डेपुटेशन से लौट रहे छत्तीसगढ़

रायपुर. 1998 बैच के आईपीएस अमित कुमार सीबीआई के डेपुटेशन से छत्तीसगढ़ लौट रहे हैं. वे सोमवार को छत्तीसगढ़ पुलिस ज्वाइन करेंगे. जानकारी के अनुसार,अमित कुमार को पुलिस महकमे में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. नई सरकार बनने के बाद ही तय होगा कि, उन्हें कौन सा पोस्ट दिया जाएगा. बता दें कि, अमित कुमार सीबीआई में एसपी, डीआईजी और संयुक्त निदेश (पॉलिसी) की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं. खास बात तो ये है कि, वे लालू यादव के चारा घोटाले की जांच टीम में भी शामिल थे. वे रायपुर समेत कई जिलों के एसपी भी रह चुके हैं.

दो हज़ार करोड़ के बांड बेचेगी छत्तीसगढ़ सरकार, 86 हज़ार करोड़ हुआ राज्य का कर्ज़ा

रायपुर। राज्य सरकार को 2 हजार करोड़ का कर्ज चाहिए। सरकार इसके लिए अपना बांड (प्रतिभूति) बेच रही है। इसके लिए वित्त विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 4 दिसंबर को जारी इस नोटिफिकेशन में सरकार ने बताया है कि बांड की बिक्री रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया (आईबीआई) के माध्यम से होगी।

बता दें कि राज्य में चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद यह दूसरी बार है जब राज्य सरकार कर्ज लेने जा रही है। इससे पहले राज्य सरकार ने नवंबर में एक हजार करोड़ कर्ज लिया है। 28 नवंबर को लिया गया यह कर्ज राज्य सरकार 7.75 प्रतिशत ब्याज दर से लौटाएगी।

राजू गुप्ता हत्याकांड में आरोपी को उम्र कैद की सजा व सह आरोपी दोषमुक्त

रायपुर। चार साल पहले सरोना में राजू गुप्ता नामक युवक की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी राहुल आहूजा को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि सह आरोपी उमेश मरसकोले के खिलाफ अपराध प्रमाणित नहीं होने पर उसे दोषमुक्त कर दिया। अतिरिक्त लोक अभियोजक आरएस भामरा ने बताया कि 13 अगस्त, 2019 की रात दस बजे केपीएस स्कूल सरोना के पास आरडीए कालोनी रायपुरा निवासी आरोपित राहुल आहूजा (20) और महादेव घाट, रायपुरा निवासी उमेश मरसकोले उर्फ चांटी (22) ने पुरानी रंजिश का बदला लेने अपने ही साथी राजू गुप्ता के पेट, पसली, गर्दन में चाकू से कई वार कर दिया था। इस हमले में गंभीर रूप से घायल राजू गुप्ता की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्जकर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ ही आठ नंवबर 2021 को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार मिंज की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

हत्या के इस केस की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विजय कुमार मिंज ने पुलिस की ओर से पेश किए गए ठोस सुबूत, गवाहों के बयान के आधार पर राहुल गुप्ता को हत्या का दोषी पाकर धारा 302 में उम्र कैद,धारा 25,27 आमर्स एक्ट में तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही एक हजार रुपये और पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

अभा सिक्ख क्रिकेट चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मैच आज

रायपुर। 15 वीं सिक्ख प्रीमियर लगेज - 2023 ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट के दो सेमीफाइनल मैच शनिवार को एसईसीआरएसए क्रिकेट ग्राउंड डब्ल्यूआरएस कालोनी में खेले जायेंगे। पहला मैच नांदेड़ व चंडीगड़ एवं दूसरा मैच रायपुर व पटियाला के बीच खेला जायेगा। इससे पूर्व आज खेले गए मैच में चंडीगड़ सिक्ख व पंजाब पटियाला ने जीत दर्ज की। मैच के अतिथि हरमीत सिंह होरा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए शुभकामनाएं दी। शुक्रवार को पहला मैच त्राल इलेवन कश्मीर व चंडीगड़ सिक्ख के बीच खेला गया। त्राल की टीम ने 18 ओवर में 9 विकेट खोकर 126 रन बनाए। जिसमें सर्वाधिक देविंदर सिंह ने 65 रन बनाए। चंडीगड़ के हरप्रीत ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट चटकाए वहीं जसक्रीत मेहरा ने 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट लिए। जवाबी पारी खेलते हुए चंडीगड़ सिक्ख ने 15.1 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 132 रन बनाकर मैच जीत लिया। रमनजीत सिंह ने 43 गेंद में 63 रन की शानदार पारी खेली वहीं प्रभजीत सिंह ने 5 चौके व 3 छक्कों की मदद से 42 गेंद में 54 रन का स्कोर किया। त्राल इलेवन कश्मीर की ओर से गुरप्रीत सिंह ने 3.1 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेट लिए।

शिकायतकर्ताओं के लिए राज्य उपभोक्ता आयोग ने की नई पहल की शुरुआत

रायपुर। छत्तीसगढ़ में उपभोक्ता के समय और पैसा बचाने के लिए राज्य उपभोक्ता आयोग ने नई पहल शुरू की है. न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया ने बताया कि आप अपना केस घर बैठे लड़ सकते हैं. सोमवार से ई-हियरिंग के माध्यम से सुनवाई होगी.

दूर-दूर से आने वाले उपभोक्ताओं का समय और पैसा की बचत होगी. मिनिमम 90 दिनों में प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा. अधिकतम पांच महीने में निराकरण किया जाएगा. उन्होंने पेंडिंग केस खत्म करना हमारा मुख्य लक्ष्य है.

न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया ने आगे बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायपुर में 795 कुल प्रकरण आया है. जिसमें से 604 मामले को निराकरण किया गया है. 191 मामला निराकृत के लिए बाकी है.

वरिष्ठ पत्रकार आलोक मिश्रा का निधन

दुर्ग। वरिष्ठ पत्रकार आलोक मिश्रा का गुरुवार निधन हो गया। वे गंभीर बीमारी के कारण श्री शंकराचार्य मेडिकल कालेज हास्पिटल,भिलाई में भर्ती थे। उनका अंतिम संस्कार दोपहर बाद किया गया। आलोक मिश्रा दुर्ग प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष थे और से प्रकाशित होने वाले प्रमुख अखबारों के ब्यूरो प्रमुख थे। उनके निधन पर दुर्ग प्रेस क्लब ने श्रद्धांजली दी।

लैंगिक असमानता दूर करने विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की दी गई जानकारी

सहेंगे नहीं, कहेंगे... चुप्पी तोड़ेंगे : 'नई चेतना - जेंडर अभियान 2.0' पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन

रायपुर। लैंगिक असमानता दूर करने भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ''नई चेतना - जेंडर अभियान 2.0'' पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से नवा रायपुर में आयोजित इस कार्यशाला में लैंगिक असमानता दूर करने विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। पुलिस, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास, श्रम तथा वन विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान के अधिकारी भी कार्यशाला में शामिल हुए। 'बिहान' के साथ काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों चैतन्य, प्रदान, ट्रिफ और पीसीआई के साथ ही 'बिहान' की दीदियों तथा राज्य व जिला स्तरीय अधिकारियों ने भी कार्यशाला में भाग लिया। लिंग आधारित भेदभाव, घरेलू हिंसा इत्यादि पर ग्रामीण परिवारों में समझ विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अभियान ''नई चेतना - जेण्डर अभियान 2.0'' प्रारंभ किया गया है। विगत 25 नवम्बर से शुरू हुए इस अभियान का क्रियान्वयन 4 दिसम्बर से 23 दिसम्बर तक छत्तीसगढ़ में भी किया जा रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना आर. ने कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए राज्य में अच्छा काम हो रहा है। 'सहेंगे नहीं, कहेंगे... चुप्पी तोड़ेंगे' नई चेतना - जेण्डर अभियान 2.0 का टैगलाइन है। उन्होंने कहा कि यह चुप्पी तोड़ने का वक्त है। महिलाओं के विरूद्ध हो रहे दुर्व्यवहार और अपराध को साझा करने का समय है। इनसे ही लैंगिक असमानताओं से जुड़ी समस्याओं का हल निकलेगा। उन्होंने कहा कि स्वसहायता समूहों की महिलाओं के इस अभियान से जुड़ने से लैंगिक असमानता को दूर करने की दिशा में तेजी से काम होगा। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की संचालक श्रीमती पद्मिनी भोई साहू ने कार्यशाला में कहा कि महिलाओं से जुड़े मामलों में उनकी निजता और भावनाओं को भी समझने की जरूरत है। महिलाओं से संबंधित प्रकरणों का सकारात्मक होकर निराकरण किया जाना चाहिए।

पुष्टिकर समाज भवन के लिए बृजमोहन ने की और 10 लाख देने की घोषणा

रायपुर। पुष्टिकर समाज के सामुदायिक भवन के लिए बृजमोहन अग्रवाल ने और 10 लाख देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मेरी कोई ताकत नहीं हैं। मुझ में कोई दम नहीं हैं। ये सब आप सभी के मत की ताकत हैं जो मुझे लगातार सेवा करने का संबल देती हैं। बूढेश्वर बाबा और भैरुनाथ बाबा के आशीर्वाद से अब प्रदेश में कमल फुल वाली भाजपा की सरकार हैं विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होगी। रायपुर के सबसे बड़े शिवालय में बूढ़ेश्वर महादेव की पूजा अर्चना कर उन्होंने अपने आठवें सार्वजनिक कार्यकाल आगाज करते हुए उन्होंने कहा की भोले बाबा ने बुलाया है। ये सब उनके ही आशीवाद का परिणाम हैं की रायपुर की जनता मुझे लगातार आशीर्वाद दे रही हैं। शहर का हर नागरिक बृजमोहन हैं और किसी भी काम के लिए जनता को भटकने की आवश्यकता नहीं हैं.

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.